राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 20 फरवरी 2026 वर्ष-9,अंक-28 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम टिप्पणी, सबको फ्री सुविधाएं बांटना गलत, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे...

मुफ्त बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, कहा-सरकारें रेवड़ी नहीं रोजगार के अवसर करें पैदा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, तमिलनाडु बिजली बोर्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है। वहीं एक मुकदमे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्यों में अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति आर्थिक विकास में बाधा डालती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत जजों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा ज्यादातर राज्य पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी विकास को छोड़कर मुफ्त सुविधाएं बांट रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा- जो लोग भुगतान नहीं कर सकते, उन्हें सहायता देना समझ में आता है। लेकिन अमीर-गरीब में फर्क किए बिना सबको मुफ्त देना गलत नीति है। इस दौरान कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा अगर सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली मिलती रही तो लोगों में काम करने की भावना कम हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं।

कोर्ट का राज्यों को दी सलाह और पूछा सवाल

वहीं कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त चीजें बांटने के बजाय, रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, भारत में हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं? क्या यह वोट पाने की नीति नहीं बन जाएगी? फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई में तय होगा कि ऐसे मुफ्त बिजली योजनाओं पर क्या नियम लागू होंगे। यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कई राज्यों में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं और इससे सरकारी खर्च बढ़ता है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगडऩे का खतरा रहता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि गरीबों की मदद जरूरी है, लेकिन बिना सोच-समझ सबको मुफ्त सुविधाएं देना देश के विकास के लिए सही नहीं है।

मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं

जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, हम भारत में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते। लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं, उनके बीच कोई फर्क किए बिना मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टिकरण की नीति नहीं है? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो-महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी

खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों किया।

बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब के बठिंडा में गुरुवार को किसानों और पुलिस के बीच उस समय जबरदस्त टकराव हो गया, जब किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई। वहीं समाना में भी हालात तनावपूर्ण रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के उग्र होने पर हालात बिगड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाज़ी हुई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। कई प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के हल्की चोटें आने की भी सूचना है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ रोष जता रहे थे। उनका आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन संवेदनशीलता नहीं दिखा रहा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। इधर, पटियाला जिले के समाना में भी हालात तनावपूर्ण रहे। वहां किसानों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद माहौल गरमा गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। पंजाब में पिछले कुछ समय से विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के प्रदर्शन जारी हैं। बठिंडा और समाना की घटनाओं ने एक बार फिर राज्य में कानून-व्यवस्था और किसान आंदोलन को लेकर बहस तेज कर दी है।

राहुल गांधी सहित 25 सांसदों की हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिरला के अपमान पर दी धमकी

-खुद को बीजेपी और करणी सेना का सदस्य बताता

जयपुर (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित 25 सांसदों की हत्या की धमकी देने वाले शख्स को राजस्थान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर धमकी वाला वीडियो वायरल होने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अपमान का आरोप लगाकर आरोपी ने जान से मरने की धमकी दी थी। उसकी पहचान राज सिंह आमेरा के रूप में हुई है। वहां खुद को करणी सेना और भाजपा का कार्यकर्ता बताकर कहता है कि राहुल गांधी को घर घुसकर गोली मार देगा। वहीं, मामले भाजपा ने साफ कर दिया हैं कि आरोपी आमेरा का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कोटा शहर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रेम नगर निवासी राज आमेरा नामक युवक कांग्रेस सांसदों और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। वीडियो में खुद को करणी सेना का बताकर शख्स ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष बिरला के चैंबर में हुई घटना का जिक्र किया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी के पहले पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी खुद को मशहूर करने के लिए इस तरह के वीडियो बनाकर वायरल करता था।

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले में गांधी परिवार और दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया। इसके साथ ही, 9 मार्च को सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को लिस्ट कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी पक्ष को और समय दिए जाने पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि उन्हें दो महीने पहले नोटिस दिया गया था। 22 दिसंबर 2025 को, हाईकोर्ट ने गांधी परिवार और अन्य को मुख्य पिटीशन के साथ-साथ ईडी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया।

एआई में पारदर्शिता जरूरी, बने सबके हित और सुख का साधनः प्रधानमंत्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को एआई शिखर सम्मेलन में विश्व के समक्ष भारत का सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का बेंचमार्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एआई को कुछ देश और कंपनियां रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की सोच रही हैं। भारत का मानना है कि एआई के लिए पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा, ÷हमें आज यह संकल्प करना चाहिए कि एआई को वैश्विक भलाई (ग्लोबल कॉम गुड) के रूप में विकसित किया जाएगा।÷

दुनिया के 20 देशों के नेताओं और 45 देशों के मंत्रियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ने एआई से जुड़ा 'मानव' विजन प्रस्तुत किया। मानव विजन का अर्थ है एम (मोरल एंड एथिकल सिस्टम), ए (अकाउंटेबल गवर्नेंस) एन (नेशनल सॉवरेन्टी) ए (एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव) वी (वैलिड एंड लेजिटीमेट)।

प्रधानमंत्री ने वर्तमान में सामने आई एआई चुनौतियों जैसे डीप फेक का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रकार खाने के सामानों पर

उसके अंदर उपयुक्त सामग्री का लेबल होता है, इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी लेबलिंग बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने एआई को मानव इतिहास का आज तक का सबसे परिवर्तनकारी नवाचार बताया और कहा कि इसकी तेजी और स्तर, अब तक हुए सभी नवाचार से कहीं ज्यादा है। ऐसे में इसके विनाशकारी प्रभाव भी हो सकते हैं जिससे बचाना जरूरी है।

ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एआई को लोकतांत्रिक करने और इसे समावेशी और सशक्त बनाने का माध्यम बनाने पर जोर देना चाहिए।

राफेल डील का विस्तार, राष्ट्रपति मैक्रॉन का ऐलान- मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे जेट्स

नई दिल्ली (एजेंसी)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने गुरुवार को भारत के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों की योजना राफेल जेट कार्यक्रम का विस्तार करना है, जिसमें भारत में सह-उत्पादन और मेक इन इंडिया भविष्य के ऑर्डरों का मुख्य आधार बनेंगे।

मैक्रों ने 'मेड इन इंडिया' राफेल पर बात की

भारत एआई शिखर सम्मेलन के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए मैक्रॉन ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' है जो पारंपरिक रक्षा संबंधों से कहीं आगे जाती है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत ने हाल ही में राफेल विमानों के लिए एक नया ऑर्डर देने और इस प्लेटफॉर्म से संबंधित औद्योगिक सहयोग को और गहरा करने की इच्छा व्यक्त की है। मैक्रों कहा कि राफेल के संबंध में, हम विस्तार करना चाहते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले राफेल 114 के नए बैच का ऑर्डर देने और सह-उत्पादन करने की इच्छा की पुष्टि की है। 'मेक इन इंडिया' इस नए ऑर्डर का मूल आधार होगा।' उन्होंने इस कदम को एक नया कदम बताया जो मौजूदा सहयोग को मजबूत करते हुए इसे और आगे ले जाता है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने रखरखाव और संरक्षा में सहयोग को मजबूत करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें विविध रखरखाव क्षमताएं और दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक औद्योगिक समझौते शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, राफेल बेहद महत्वपूर्ण है। मैक्रों ने कहा कि पनडुब्बियों सहित अन्य प्रमुख रक्षा क्षेत्रों में भी सहयोग के समान मॉडल तलाशे जा सकते हैं, और उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग के एक नए युग के निर्माण के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में एयरोस्पेस साझेदारी के विस्तार की ओर इशारा किया।

दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंची प्रियंका गांधी, मां कामाख्या का लिया आशीर्वाद

गुवाहाटी (एजेंसी)। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में दो दिवीसय दौर पर पहुंचीं। उनका मकसद आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को तेज करना है।

बोरझार में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के तुरंत बाद, प्रियंका गांधी पूजा करने के लिए सीधे कामाख्या मंदिर के लिए रवाना हो गयीं। हवाई अड्डे पर असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी (एपीसीसी) के अध्यक्ष एवं सांसद गौरव गोगोई समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंदिर जाने के बाद, वह स्क्रीनिंग से जुड़ी कई बैठक की अध्यक्षता करने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के लिए रवाना हुईं। प्रियंका गांधी असम में एक ऐसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया की निगरानी कर रही हैं जिसे पार्टी नेताओं ने 'अपूर्व और संरचित' बताया

है। वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह पहली बार है जब कांग्रेस राज्य में इतनी व्यापक और परामर्शात्मक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया कर रही है। असम कांग्रेस के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि प्रियंका आने वाले महीनों में कई बार राज्य के दौरे पर आएंगी ताकि प्रगति की समीक्षा कर सकें, जमीन से प्राप्त फीडबैक का आकलन कर सकें और राज्य इकाई और केंद्रीय नेतृत्व के बीच निकट समन्वय सुनिश्चित कर सकें।

समुद्री डकैती, आतंकवाद, साइबर समस्या बड़ी चुनौतियां, अकेले कोई नौसेना सामना करने में अक्षमः राजनाथ सिंह

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित नौसेना के अभ्यास 'मिलन-2026' को संबोधित करते हुए कहा कि आज समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी, साइबर कमजोरियां और जरूरी आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाएं वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जिससे मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों की आवश्यकता अधिक बार और व्यापक रूप से पड़ रही है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एक नौसेना, चाहे वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो, इन सभी चुनौतियों का अकेले सामना नहीं कर सकती। इसलिए नौसेनाओं के बीच सहयोग अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। इस वर्ष 74 देशों की भागीदारी के साथ 'मिलन-2026' अब तक का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी आयोजन बन गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक समुद्री समुदाय भारत को एक भरोसेमंद और जिम्मेदार समुद्री भागीदार के रूप में देखता है। आज की विशिष्ट जिम्मेदारियां अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपेक्षा करती हैं कि वह परस्पर सम्मान की भावना से मिलकर चुनौतियों का समाधान करे।

शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में मची भगदड़, किले की टूटी रेलिंग, कई घायल

पुणे। पुणे जिले के जुन्नार में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर समारोह में भारी भीड़ के चलते रेलिंग टूट गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। एसपी ने बताया कि इस घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शिवनेरी किला परिसर में हुई, जो शिवाजी महाराज का जन्मस्थान माना जाता है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा की ओर जाने वाले हिस्से में भीड़ अचानक बढ़ गई। पीछे से धक्का लगने पर आगे खड़े लोगों का संतुलन बिगड़ गया और कुछ लोग नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत भीड़ को कंट्रोल किया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है।

संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं, यह कहना गलत संघ बीजेपी को चलाता: भागवत

-संयुक्त परिवार भले कम हो गए हों लेकिन रिश्तों की भावना बनी रहनी चाहिए

लखनऊ (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला में संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान भागवत ने बुधवार को कहा कि संघ बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं और पार्टी में सियासी तौर पर आगे भी बढ़े हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने बीजेपी और आरएसएस के संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक अलग-अलग क्षेत्रों में जाते हैं, उसमें से कुछ स्वयंसेवक राजनीति में भी सक्रिय होते हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले लोग ही आरएसएस का विरोध करते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहन भागवत ने परिवार और संस्कार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार भले कम हो गए हों, लेकिन रिश्तों की भावना बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन परिवार को साथ बैठना चाहिए। बच्चों को संस्कार घर और स्कूल दोनों से मिलते हैं। संघ प्रमुख ने हिंदू समाज में अपार शक्ति है, लेकिन स्वार्थ में फंसा है। यदि समाज एकजुट हो जाए तो देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। जाति व्यवस्था को पुराना बताते हुए उन्होंने कहा कि अब जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि पहले यह काम के आधार पर थी, लेकिन समय बदल चुका है। जाति की दीवारें टूट रही हैं। भागवत ने कहा कि हम सब भारत माता की संतान हैं। रंग, रूप या जाति अलग हो सकती है, लेकिन अपनापन बना रहना चाहिए। इसी भावना से छुआछूत जैसी बुराई खत्म हो सकती है। जाति व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। जाति नाम की कोई व्यवस्था अब रहनी नहीं चाहिए। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि असली चिंता यह होनी चाहिए कि मंदिरों की व्यवस्था और नियमित पूजा-पाठ की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि सिख समाज अपने गुरुद्वारों का संचालन व्यवस्थित ढंग से करता है। धर्माचार्यों और समाज को इस दिशा में आगे आना चाहिए।

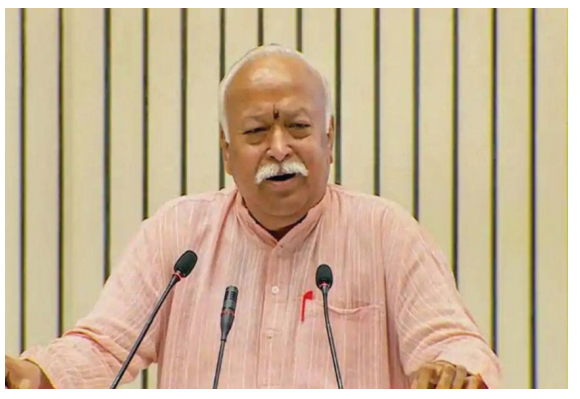

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मानवाधिकारों का सम्मान करना और संसाधनों का निष्पक्ष वितरण के लिए विश्व सामाजिक न्याय दिवस

(लेखक––संजय गोस्वामी)

(विश्व सामाजिक न्याय दिवस– 20 फरवरी, 2026 पर विशेष)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अनिवार्य बनाते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय शामिल हैं। सामाजिक न्याय वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। यह समाज में संसाधनों, अधिकारों और विशेषाधिकारों के निष्पक्ष और समान वितरण पर बल देता है, साथ ही हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली व्यवस्थागत बाधाओं को दूर करने पर भी जोर देता है। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ व्यक्तियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए, उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी हों और वे जाति, लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सामुदायिक जीवन में पूर्णतः भाग ले सकें। इसके प्रमुख तत्वों में समानता (आवश्यकता–आधारित निष्पक्षता), पहुँच, सहभागिता और मानवाधिकार शामिल हैं। सामाजिक न्याय विश्वास का निर्माण करके, वैधता को मजबूत करके और प्रत्येक सदस्य की क्षमता को उजागर करके एक शांतिपूर्ण, समावेशी और लचीले समाज को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य एक समावेशी समाज का निर्माण करना है जो जाति, लिंग, वर्ग, धर्म या शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य करता है। इसमें सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों का सम्मान करना और संसाधनों का निष्पक्ष वितरण करना शामिल है। सामाजिक न्याय आर्थिक असमानता को कम करने और शोषित और कमजोर समूहों को विकास की मुख्यधारा में एकीकृत करने का एक सक्रिय प्रयास है। यह हाशिए पर पड़े समूहों को सुरक्षा और समानता प्रदान करके समाज में स्थिरता बनाए रखने, शांति को बढ़ावा देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 10 जून, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया। महासभा यह स्वीकार करती है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांति और सुरक्षा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर, 2007 को महासभा ने घोषणा की कि अपने 63वें सत्र से, 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2026 में, यह दिवस सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति एक नई प्रतिबद्धता विषय के तहत मनाया जाएगा। इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन और दोहा राजनीतिक घोषणापत्र को अपनाने के बाद हो रहा है। 1995 के कोपेनहेगन घोषणापत्र के सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए, सदस्य देशों ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी उन्मूलन, पूर्ण और उत्पादक रोजगार सुनिश्चित करना, सभी के लिए सम्मानजनक काम को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना सामाजिक विकास के परस्पर जुड़े स्तंभ हैं। वैश्वीकरण और बढ़ती परस्पर निर्भरता—व्यापार, निवेश, पूंजी प्रवाह और सूचना प्रौद्योगिकी सहित तकनीकी प्रगति द्वारा सुगम—वैश्विक आर्थिक विकास और विश्व स्तर पर जीवन स्तर में सुधार के लिए नए अवसर पैदा करती है। फिर भी, वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और समाजों के भीतर और उनके बीच असमानता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्णतः एकीकृत होने और समान स्तर पर भाग लेने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महासभा स्वीकार करती है कि सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांति और सुरक्षा स्थापित करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी स्वीकार करती है कि शांति, सुरक्षा, मानवाधिकारों के सम्मान और मौलिक स्वतंत्रता के बिना इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और निष्पक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए, यह सभ्य कार्य मानकों पर आधारित निष्पक्ष वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, यह सभी के लिए अधिक रोजगार के अवसर और आय उत्पन्न करने की एक उत्पादक रणनीति के रूप में सतत उद्यम विकास के महत्व पर बल देता है दोहा राजनीतिक घोषणा (2025) और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग (छस्ष्ष्छ) के 64वें सत्र (फरवरी 2026) के परिणामों के आधार पर, 2026 का स्मारक एजेंडा सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन और समावेशी नीतियों को ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य किसी को पीछे न छोड़ने की प्रतिबद्धता को व्यावहारिक, डेटा–आधारित कार्यों में बदलना है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों, गरिमापूर्ण कार्य, डिजिटल समावेशन और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सामाजिक विकास और न्याय को आगे बढ़ाने के लिए समन्वित, न्यायसंगत और समावेशी नीतियों की आवश्यकता है जो सामाजिक पहलुओं को व्यापक आर्थिक, श्रम, जलवायु, डिजिटल और औद्योगिक रणनीतियों में शामिल करें। इस वर्ष का विषय वर्तमान और उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए प्राप्त प्रगति को स्वीकार करता है। यद्यपि गरीबी कम करने, शिक्षा में सुधार करने और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी संरचनात्मक असमानताओं, अनौपचारिक श्रम बाजारों, लैंगिक असमानताओं और संस्थानों में जनता के घटते विश्वास जैसे मुद्दे समावेशी और सतत विकास में बाधा बने हुए हैं। परिणामस्वरूप, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में नीतिगत सामंजस्य बढ़ाने, बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक नीति निर्माण में समानता और एकजुटता को प्राथमिकता देने के लिए नए सिरे से समर्पण की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, सदस्य देशों ने ऐसे व्यापक आर्थिक ढाँचों की आवश्यकता की पुष्टि की जो सम्मानजनक कार्य और उचित वेतन को बढ़ावा दें, श्रम बाजार संस्थानों को सुदृढ़ करें और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने, अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन का समर्थन करने और डिजिटल एवं हरित अर्थव्यवस्थाओं की ओर निष्पक्ष एवं समावेशी बदलाव को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सामाजिक भागीदारों और नागरिक समाज के बीच बेहतर सहयोग संसाधनों को जुटाने, नीतिगत नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ पर आई है, जो वैश्वीकरण में एक मजबूत सामाजिक आयाम को एकीकृत करने के महत्व पर बढ़ती सहमति को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सभी क्षेत्रों में नीति निर्माण में सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने और जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपांतरण और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हैं। 10 जून, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणा को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। यह 1919 के आईएलओ संविधान में संगठन की स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों और नीतियों का तीसरा प्रमुख समूह है। यह 1944 की फिलाडेल्फिया घोषणा और 1998 की कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर घोषणा पर आधारित है। 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के संदर्भ में आईएलओ के वर्तमान जनादेश के दृष्टिकोण को समाहित करती है। यह ऐतिहासिक घोषणा आईएलओ के मूल्यों की दृढ़ता से पुष्टि करती है। यह वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग की रिपोर्ट के बाद शुरू किए गए त्रिपक्षीय परामर्शों का परिणाम है। इस दस्तावेज़ को अपनाकर, 182 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने वैश्वीकरण के बीच प्रगति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईएलओ) की त्रिपक्षीय संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया है। उन्होंने सभ्य कार्य एजेंडा के माध्यम से इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आईएलओ की क्षमता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

वैश्वीकरण और बढ़ती परस्पर निर्भरता–व्यापार, निवेश, पूंजी प्रवाह और सूचना प्रौद्योगिकी सहित तकनीकी प्रगति द्वारा सुगम–वैश्विक आर्थिक विकास और विश्व स्तर पर जीवन स्तर में सुधार के लिए नए अवसर पैदा करती है। फिर भी, वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, सामाजिक बहिष्कार और समाजों के भीतर और उनके बीच असमानता जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्णतः एकीकृत होने और समान स्तर पर भाग लेने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

संपादकीय

अपराध की मंशा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना, जिसमें 'बलात्कार के प्रयास' की परिभाषा बदल दी गई थी, केवल एक कानूनी सुधार मात्र नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। यह न्यायिक संवेदनशीलता और गंभीर मामलों मे न्यायिक दृष्टि की स्पष्टता की पुनः पुष्टि भी है। सर्वोच्च अदालत ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही धारा 376 आईपीसी के तहत आरोप बहाल करके, इस बात पर भी बल दिया कि अपराध के इरादे को, प्रत्यक्ष कृत्य के साथ कमतर नहीं माना जा सकता है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस बाबत जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं, जिसे किसी सभ्य समाज की मान्यताओं के प्रतिकूल माना गया था। दरअसल, हाई कोर्ट ने माना था कि एक नाबालिग के उरोज पकड़ना, उसके पायजामे की डोरी ढीली करना और उसे घसीटकर ले जाने का प्रयास दुराचार की तैयारी थी, न कि बलात्कार का प्रयास, क्योंकि इसमें अपराध की दिशा में कोई सीधा कदम नहीं उठाया गया था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की संकीर्ण व्याख्या के खिलाफ समाज में प्रतिक्रिया होनी ही थी। कहीं न कहीं इस तंग व्याख्या से अपराधी के जघन्य इरादे और प्रयास की अवधारणा को कमजोर करने का जोखिम भी था। निस्संदेह, इस तरह की व्याख्या से महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद ही होते। जाहिर है इस तरह की सोच कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह सुखद ही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संकीर्ण व्याख्या वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सार्थक हस्तक्षेप किया है। दरअसल, आपराधिक कानून में, प्रयास तब माना जाता है, जब किसी अपराध की तैयारी उस कृत्य को अंजाम देने में बदल जाती है। जो कि इच्छित अपराध के निकट होती है। इस मामले में आरोप– शारीरिक छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने और जबरन घसीटना, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो स्पष्ट रूप से यौन उत्पीड़न की ओर एक सुनियोजित कदम की पुष्टि कर देते हैं। जिसे केवल पीड़िता के करुण क्रंदन सुनने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के हस्तक्षेप से ही रोका गया। निस्संदेह, इसके विपरीत मानना यौन हिंसा की वास्तविकताओं और नाबालिगों की असुरक्षा को अनदेखा करना ही होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह फैसला आरोपों की गंभीरता की पुष्टि करता है। ताकि पूर्व सुनवाई में साक्ष्यों की उचित संदर्भ में जांच की जा सके। ऐसे वक्त में जब देश की कई अदालतों के लैंगिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना हो रही थी, यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि कानूनी तर्क को संवैधानिक मूल्यों को बनाये भी रखना चाहिए। निर्विवाद रूप से, जिनका उद्देश्य किसी सभ्य समाज में नागरिकों को आसन्न खतरे से भी बचाना ही होता है। बहरहाल, इस प्रकरण में यह सार्थक हस्तक्षेप इस बात की पुष्टि भी करता है कि कानून बच्चों को न केवल अपराधियों द्वारा अंजाम दिए जा चुके अपराधों से बल्कि भविष्य में आसन्न अपराधों से भी बचाता है। इस प्रकरण के बाद कहा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल न्यायिक जवाबदेही में संतुलन स्थापित किया, बल्कि आखिरकार आम लोगों के विश्वास को भी बहाल किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया को न्याय के नैसर्गिक नियमों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। जो देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति आम आदमी के भरोसे को बढ़ाने वाला भी होगा। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जब व्यक्ति समाज में चारों तरफ से व सिस्टम से निराश हो जाता है तो न्याय की चौखट उसकी उम्मीद की अंतिम किरण होती है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 का व्यापक विरोध क्यों ज़रूरी है

— संजय चावला

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025' को सुधार के नाम पर एक 卐एकीकृत नियामक व्यवस्था卐 के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन इसके भीतर छिपे प्रावधान विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, संघीय ढांचे, अकादमिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक शिक्षा की आत्मा पर गंभीर प्रहार करते हैं। राज्यसभा में डॉ. जॉन ब्रिटास सहित अनेक सांसदों, शिक्षाविदों और शिक्षक संगठनों ने जिन आशंकाओं को उठाया है, वे महज़ राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और शैक्षिक लोकतंत्र से जुड़ी गहरी चिंताएँ हैं।

केंद्रीकरण बनाम स्वायत्तता: विश्वविद्यालयों की आज़ादी दांव पर

विधेयक का मूल स्वर एक सुपर–रेगुलेटर खड़ा करना है, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा से जुड़े नियामक निकायों को समेटकर व्यापक अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में सौंपी जाएगी। सुनने में यह 卐सरलीकरण卐 लगता है, पर व्यावहारिक अर्थ है—

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की शैक्षणिक स्वायत्तता का क्षरण,

नियमन पर कार्यपालिका का बढ़ता वर्चस्व,

और निर्णय–प्रक्रिया का राजनीतिक रंग लेना।

शिक्षा का सार आलोचनात्मक सोच, असहमति की गुंजाइश और बौद्धिक स्वतंत्रता में निहित है। जब नियमन और हस्तक्षेप एक ही केंद्र से संचालित होंगे, तो अकादमिक विविधता सिकुड़ेगी और संस्थानों पर अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ेगा।

संघीय ढांचे पर चोट: राज्यों की भूमिका हाशिये पर

भारतीय संविधान शिक्षा को साझा दायित्व मानता है। इसके बावजूद इस बिल की संरचना में राज्यों का प्रतिनिधित्व सीमित है और नियुक्तियों में केंद्र का निर्णायक प्रभाव है। यह सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है।

राज्य सरकारें अपने सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप विश्वविद्यालयों की नीतियाँ बनाती रही हैं। केंद्रीकरण का परिणाम होगा—

पाठ्यक्रमों में एकरूपता का दबाव,

स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी,

और राज्यों की नीतिगत स्वायत्तता कम करना।

यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन का प्रश्न है।

कार्यपालिका का अति–हस्तक्षेप: नियामक से नियंत्रक तक

विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत सरकार नियामक निकायों को निर्देश देने, भंग करने या पुनर्गठित करने का अधिकार रखती है। इससे नियामक संस्थाएँ स्वतंत्र प्रहरी नहीं, बल्कि सरकारी आदेशों की वाहक बन सकती हैं।

वित्तीय निर्भरता: सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की सौदेबाज़ी

प्रस्तावित निधि–व्यवस्था में केंद्र से मिलने वाले अनुदानों की भूमिका निर्णायक होगी। इसका निहितार्थ है कि विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्वतंत्रता घटेगी और वे केंद्रीय प्राथमिकताओं पर अधिक निर्भर होंगे।

ग्रामीण, हाशिये के समुदायों या क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वाले संस्थान पहले ही संसाधनों की कमी से जूझते हैं। नई व्यवस्था में उन्हें फंडिंग के लिए नीतिगत 卐अनुरूपता卐 दिखानी पड़ सकती है—जो शिक्षा को सार्वजनिक हित से हटाकर अनुदान–निर्भर आज्ञाकारिता की ओर ले जाती है।

भाषाई–सांस्कृतिक विविधता पर दबाव

विधेयक की भाषा और नामकरण को लेकर भी आपत्तियाँ उठी हैं। भारत बहुभाषी देश है। उच्च शिक्षा की नीतियाँ सांस्कृतिक बहुलता को प्रतिबिंबित करें—यह अपेक्षा स्वाभाविक है। जब प्रतीकात्मक स्तर पर भी एकरूपता थोपी जाती है, तो संदेश जाता है कि विविधता के लिए स्थान सीमित है। शिक्षा में यह रुझान वैचारिक संकीर्णता को बढ़ावा देता है।

मानकीकरण का भ्रम: विविधता का क्षरण

एकीकृत ढांचा गुणवत्ता सुधार का दावा करता है, पर एक–सा मानक विविध शैक्षणिक संदर्भों पर लागू करना व्यावहारिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। भारत के विश्वविद्यालयों की ताकत उनकी बहुरंगी परंपराओं में है—कहीं अनुसंधान की सघनता, कहीं क्षेत्रीय अध्ययन, कहीं सामाजिक न्याय पर केंद्रित शिक्षण। अत्यधिक मानकीकरण से यह विविधता समतल हो जाएगी और नवाचार की गुंजाइश घटेगी।

निष्कर्ष: सुधार चाहिए, केंद्रीकरण नहीं

उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन सुधार का रास्ता संवाद, सहमति और स्वायत्तता से होकर जाता है—आदेश और नियंत्रण से नहीं।

शिक्षक, छात्र, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और नागरिक समाज—सबको मिलकर ऐसे प्रावधानों का विरोध करना चाहिए जो शिक्षा को लोकतांत्रिक सार्वजनिक संस्थान से बदलकर केंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र बना दें।

सच को छुपाने का परिणाम

एक बार की बात है। एक व्यक्ति का पुत्र कमाने के लिए विदेश गया। विदेश कमाने गए पुत्र ने अपने पिता को एक बहुत ही सुंदर अंगूठी भेजी। पत्र में उसने लिखा, 'पिताजी! आपको मैं एक अंगूठी भेज रहा हूं। उसका मूल्य है पांच हजार रुपए। मुझे सस्ते में मिल गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए खरीद ली' बेटे द्वारा भेजी गई अत्यंत सुंदर अंगूठी पाकर पिता प्रसन्न हो गया। पिता ने बड़े शौक से वह अंगूठी पहन ली। अंगूठी बहुत ही चमकदार और सुन्दर थी। बाजार में पिता को कई मित्र मिले। नई अंगूठी को देख कर सबने पूछा, 'यह कहां से आई?' पिता ने कहा, 'मेरे लड़के ने विदेश से भेजी है। इसे खरीदने में उसने पांच हजार रुपए खर्च किए' पिता का एक मित्र बोला, 'क्या इसे बेचोगे? मैं इस अंगूठी के पचास हजार रुपये दूंगा।' पिता ने सोचा, पांच हजार की अंगूठी के पचास हजार रुपये मिल रहे हैं। इतने रुपयों में ऐसी दस अंगूठियां आ जाएंगी। उसने अंगूठी निकाल कर दे दी और अपने मित्र से पचास हजार रुपए ले लिए। फिर उसने पुत्र को पत्र लिखा, 'तुमने शुभ मुहूर्त में अंगूठी भेजी। उसे मैंने पचास हजार रुपए में बेच कर पैंतालीस हजार रुपए का लाभ अर्जित कर किया'। लौटती डाक से पुत्र का पत्र आया, 'पिताजी! संकोच और भयवश मैंने आपको पिछले पत्र में सच्चाई नहीं लिखी थी। वह अंगूठी एक लाख की थी' यह सत्य को झुठलाने का परिणाम था।

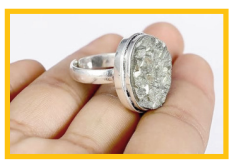

विचार मंथन

एआई समिट की चमक और ज़मीनी हकीकत

(लेखक–सनत जैन)

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर बड़े–बड़े दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्ष एआई विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, खबरों के अनुसार उसमें से लगभग 800 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को दर्शाता है। जब देश में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। मंचों से डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, सरकार की इस मामले में वास्तविक सोच क्या है? सरकार ने एआई में शोध के लिए किस तरह की नीतियां बनाई हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शोध के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। इस दौड़ में कैसे भारत आगे रहेगा। इसकी कोई वास्तविक सोच दिख नहीं रही है। एआई को लेकर भारत सरकार भी सपने देख रही है और वही सपना लोगों को दिखा रही है। विश्वविद्यालयों और आईटी सेक्टर को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। शोध के लिए पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार को बजट में जो धन उपलब्ध कराना था, उसे बढ़ाने के स्थान पर और कम किया है। शोध संस्थानों में बुनियादी ढांचा, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन और दीर्घकालिक अनुदान की कमी होने के कारण शोध लगभग लगभग बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को पर्याप्त प्रोत्साहन नही मिलेगा, तो स्वदेशी एआई तकनीक के साथ कदमताल कर पाना संभव नहीं होगा। भारत एक बाजार बनेगा। जहां पर विदेश से आयातित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा और रोजगार के अवसर विदेशों को देने का काम करेंगे। एआई समिट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी स्वागत योग्य है। भारत सरकार यदि भारत को एक उपभोक्ता बाजार बनाना चाहती है तो यह भारत सरकार की सोच है। भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए पलक पावड़े बिछाती है। भारतीय कंपनियों और भारतीय शोधकर्ताओं के ऊपर सरकार को विश्वास ही नहीं है। सरकार जो नीतियां बनाती है उनके क्रियान्वयन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कि भारतीय शोधकर्ता और भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के मुकाबले में पिछड जाती हैं। यह स्थिति दीर्घकालिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। दुनिया की अग्रणी कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी–बड़ी कंपनियों को भारतीय राजनेता और भारतीय नौकरशाह दामाद की तरह स्वागत करते हैं। भारत सरकार का हर काम इन्हीं कंपनियों को सौंपा जाता है। इनसे अच्छे उत्पादन यदि भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करते हैं। उन्हें सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है, जिसके कारण वह विदेशो में जाकर अपना करियर बनाने के लिए विवश होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला एवं अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के साथ सरकारी संरक्षण को लेकर भारतीय एवं वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारत में एआई तकनीकी का विस्तार स्वाभाविक है रूप से समय की मांग है। भारत सरकार को विदेशी कंपनियों के साथ–साथ समानांतर अवसर उपलब्ध कराकर स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। अन्यथा भारत का आयात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आयात में खर्च होगी। व्यापार में आयात और निर्यात के अंतर का घाटा बढ़ता जाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा। रक्षा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन में भारत का एआई में सीमित उपयोग चिंता का विषय है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्र एआई को रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं, एआई में शोध के कई छोटे–छोटे देश भारत सरकार से ज्यादा शोध के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। भारत का सबसे कम बजट शोध के लिए है। भारत सरकार को इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। केवल घोषणाओं से तकनीकी के साथ विकास और आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, रुपये की गिरती कीमत के आर्थिक संकेतक यह बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम कितने दबाव में हैं। वर्तमान स्थिति में भी यदि तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ती है, तो भारत में महंगाई, बेरोजगारी एवं सामाजिक आर्थिक संतुलन और भी कमजोर होगा। भारत में लाखों की संख्या में स्नातक और परास्नातक बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। वह सरकारी चपरासी की नौकरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बाद भी हम उन्हें तकनीकी ज्ञान और रोजगार के अवसर से नहीं जोड़ पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों को विचारधारा के प्रचार–प्रसार का केंद्र बनाने की स्थान पर विश्वविद्यालयों को नवाचार और अनुसंधान केंद्र के रूप में सशक्त करना समय की सबसे बड़ी चुनौती है। एआई केवल बाजार नहीं, भविष्य के सामाजिक विकास रक्षा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्रांति के लिए एक शक्ति है। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो उसे केवल उपभोक्ता और बाजार उपलब्ध नहीं कराना है। बल्कि भारत को हर क्षेत्र में निर्माता बनाने की दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों को खुली छूट देनी होगी। शोध के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी होगी। भारत के अंदर ही उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सरकार जो नीतियां बना रही हैं उसका वास्तविक लाभ भारतीयों को मिल रहा है या नहीं यह देखने का काम भी सरकार का है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डॉलर ने छीन लिया, जीएसटी कटौती का फायदा ?

महंगाई बढी-कर्ज बढा मांग घटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी की थी। सरकार का मानना था। टैक्स में कमी करने का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिसका असर बाजार पर पड़ेगा। उत्पादन एवं मांग बढ़ेगी। सरकार के राजस्व में जो कमी होगी, उसकी भरपाई भी हो जाएगी। पिछले कुछ महीनो में जिस तरह से रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा होता जा रहा है। उसके कारण जीएसटी की दरों को कम करने का जो फायदा सरकार ने देखा था। वह तो हुआ नहीं, उल्टे सामान और महंगे हो गए हैं। औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं का कहना है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के कारण जो सामान विदेश से आयात हो रहा है। उसके कारण कीमतें पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई हैं। जिसके कारण स्वदेशी बाजार में उत्पाद की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। जिसके कारण मांग कम होती जा रही है। लोगों की क्रय शक्ति लगातार कम हो रही है। उपभोक्ता बाजार में डिटर्जेंट, हेयर ऑयल ,चॉकलेट ,नूडल्स और अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के दाम भी काफी बढ़े हैं। सौंदर्य प्रसाधन एवं अन्य सामान भी महंगा हो रहा है। रोजमर्रा उपयोग में आने वाली चीज महंगी होती जा रही हैं। एफएमसीजी कंपनियां 2 से 5 फीसदी तक कीमतें बढ़ाने के लिए विवश हैं। उत्पादित सामान की लागत बढ़ती जा रही है। बिक्री कम हो रही है। इसका असर औद्योगिक संस्थानों और व्यापारिक संस्थाओं को उठाना पड़ रहा है। डॉलर ने सब गुड गोबर कर दिया है। यह चर्चा में व्यापारिक जगत कहने लगा है।

भारत की भूमिका अहम, एआई में अवसर और जोखिम समान- एंथ्रोपिक

नई दिल्ली । एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि एआई मॉडल के स्वायत्त व्यवहार, संभावित दुरुपयोग और आर्थिक विस्थापन से जुड़े जोखिमों के बीच भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमोदेई ने बताया कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल साउथ के लिए मानक स्थापित किए हैं और तकनीकी एवं मानवीय लाभों के प्रसार में मदद की है। उनका मानना है कि भारत वैश्विक एआई नीति और नैतिक उपयोग के निर्धारण में अहम योगदान दे सकता है। अमोदेई के अनुसार, एआई प्रणाली बीमारियों का इलाज कर सकती हैं, मानव स्वास्थ्य सुधार सकती हैं और अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकती हैं। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर सभी के लिए बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि, उन्होंने एआई के स्वायत्त निर्णय, दुरुपयोग और आर्थिक विस्थापन की संभावनाओं पर चिंता जताई। अमोदेई ने चेताया कि ये जोखिम अवसरों के साथ मौजूद हैं और इसका संतुलित प्रबंधन आवश्यक है।

निसान का 2026-27 में 2 लाख वाहनों की बिक्री- निर्यात का लक्ष्य

नई दिल्ली । जापानी ऑटोमेकर निशान ने भारत में अपनी पुनरुत्थान योजना के तहत 2026-27 में घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों में 1,00,000 यूनिट का लक्ष्य रखा है। अप्रैल 2025-26 तक कंपनी ने भारत में कुल 89,987 वाहन बनाए, जिनमें से 17,662 वाहन घरेलू बाजार में बिके और 68,091 वाहनों को विदेशों में भेजा गया। कई वर्षों तक मुख्य रूप से मॉडल मैग्नाइट पर निर्भर रहने के बाद, निसान ने अब अपने भारतीय पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। मंगलवार को लॉन्च हुई नई 7-सीटर मल्टी-पर्पस व्हीकल ग्रेविट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.65 लाख रुपये है। यह कदम कंपनी की भारत में सक्रिय प्रतिस्पर्धा और ग्राहक विकल्प बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने निर्णय लिया है कि हर जगह मजबूत होने के बजाय मुख्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और भारत को वैश्विक रणनीति में एक प्रमुख बाजार और विकास स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते जैसे यूके और यूरोपीय संघ के साथ, निसान के निर्यात लक्ष्यों के लिए सहायक हो सकते हैं। भारत-यूएई व्यापार समझौते का कंपनी पहले ही लाभ उठा चुकी है।

टाटा समूह एआई और चिप निर्माण में भारत में बनाएगा नई मिसाल

- टाटा समूह ने कहा, कंपनी पूरे तकनीकी स्टैक में कृत्रिम मेधा को अपनाने की प्रक्रिया में है

मुंबई । टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि कंपनी पूरे तकनीकी स्टैक में कृत्रिम मेधा (एआई) को अपनाने की प्रक्रिया में है। समूह सिलिकॉन से लेकर सिस्टम, एआई-तैयार डेटा सेंटर, एप्लिकेशन और एआई एजेंट तक हर स्तर पर एआई तैयार कर रहा है। चंद्रशेखरन ने बताया कि टाटा समूह चिप और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। प्रत्येक उद्योग के लिए अलग चिप विकसित की जाएगी, जिसमें सबसे पहले मोटर वाहन क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि की सराहना की। समूह भारत का पहला बड़े पैमाने का एआई-अनुकूलित डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसे अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण और इन्फरेंस के लिए तैयार किया गया है। ओपनएआई के साथ साझेदारी में 100 मेगावाट क्षमता के पहले चरण का निर्माण होगा, जिसे बाद में 1 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। एएमडी के साथ सहयोग से वैश्विक मानकों के अनुरूप टिकाऊ एआई अवसंरचना विकसित होगी। समूह का एआई ढांचा विविध भारतीय डेटा संपत्तियों पर आधारित होगा, ताकि बुनियादी मॉडल के ऊपर भारतीय संदर्भों के अनुसार बुद्धिमत्ता उपलब्ध कराई जा सके। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस मिलकर उद्योगों के लिए एआई ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं। हर उद्योग के लिए एजेंटिक समाधान तैयार किए जाएंगे और वैश्विक उद्यमों तक पहुंचाए जाएंगे।

विदेशी निवेशकों ने 15 दिन में निकाले 10,956 करोड़

मुंबई । फरवरी के पहले 15 दिनों में विदेशी निवेशकों (एफआईआई) ने भारतीय आईटी शेयरों से 10,956 करोड़ रुपए की निकासी की। जनवरी 2026 में 5.34 लाख करोड़ रुपए थी, जो घटकर 4.49 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी दो हफ्तों में 16 फीसदी की गिरावट। निवेशकों को डर है कि जेनरेटिव एआई ऑटोमेशन और कोडिंग में दक्ष हो रहा है, जिससे पारंपरिक मैनपावर आधारित सेवाओं की मांग घट सकती है। दिग्गज कंपनियां इंफो सिस, टाटा कंसल्टेंसी स विंसेज, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा इसी मॉडल पर निर्भर हैं। म्यूचुअल फंड्स का निवेश घटकर 3.04 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे लगभग 50,000 करोड़ रुपए की वैल्यू में कमी आई। एफआईआई ने कैपिटल गुड्स में 8,032 करोड़ रुपए फाइनेंशियल सर्विसेज में 6,175 करोड़ रुपए और मेटल व माइनिंग में 3,279 करोड़ रुपए का निवेश किया। निवेशक फिलहाल इंफास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को सुरक्षित मान रहे हैं।

रोजमर्रा की चीज़ें होंगी महंगी, 3-5 फीसदी तक बढ़ सकती हैं कीमतें

नई दिल्ली । आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों पर महंगाई की तलवार लटकने लगी है। साबुन, डिटर्जेंट, बिस्कुट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कीमतों में 3-5 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है। यह बढ़ोतरी पिछले साल सितंबर में मिली जीएसटी राहत खत्म होने और कच्चे माल की महंगाई के कारण हो रही है। साबुन और डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाला पैराफिन और सर्फेक्टेंट महंगा हो गया है। साथ ही नारियल तेल के दाम पिछले एक साल में लगभग दो गुना बढ़ गए हैं। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92.02 रुपए पर पहुंच गया, जो ऐतिहासिक निचला स्तर है। इससे विदेश से आयात किए जाने वाले सामान जैसे बादाम, ओट्स और मूसली महंगे हो गए हैं। बीते साल सितंबर में सरकार ने जीएसटी में राहत दी थी, जिससे कीमतें कम थीं। अब उस राहत का असर खत्म होने से कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं।

कौन-सी चीज़ें महंगी होंगी?

* होम केयर- सर्फ एक्सेल, रिन, विम, डोमेक्स - 3-5 फीसदी
* पर्सनल केयर- वाटिका हेयर ऑयल, डाबर - 2 फीसदी
* खाद्य पदार्थ- बिस्कुट, चॉकलेट, नूडल्स, ओट्स - 2-4 फीसदी
* पेय पदार्थ- टाटा टी, रियल जूस - सीजनल बदलाव

शेयर बाजार में हाहाकार...बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर

बाजार, सेंसेक्स 1236 अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे

निवेशकों के डूबे 8 लाख करोड़

नई दिल्ली।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच गुरुवार को भारतीय बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। लगातार तीन दिनों से जारी तेजी का सिलसिला रुकते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1236.11 अंक या 1.48 प्रतिशत गिरकर 82,498.14 पर बंद हुआ। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 365.00 अंक या 1.41 प्रतिशत गिरकर 25,454.35 पर बंद हुआ। मार्केट की इस बिकवाली में मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों को ज्यादा नुकसान हुआ। निवेशकों के करीब-करीब 8 लाख करोड़ रुपये डूब गए। शेयर बाजार की इस गिरावट में बीएसई की बड़ी लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप काफी कम हो गया। बीते कारोबारी दिन में बीएसई का मार्केट कैप जो पिछले सेशन में 472 लाख करोड़ रुपये था। वह घटकर 464 लाख करोड़ रुपये हो गया। यानी निवेशकों को भारी नुकसान हो गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी, इटरनल और पावरग्रिड प्रमुख रूप से पिछड़ने वाली कंपनियां रहीं।

मुनाफावसूली का दिखा असर

हालिया बढ़त के बाद घरेलू बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी रखी। बजट, भारत-अमेरिका समझौता और आरबीआई की नीति जैसे बड़े आर्थिक कारणों के खत्म होने और तीसरी तिमाही के नतीजों का दौर पूरा होने के बाद, नए घरेलू कारणों की कमी की वजह से बाजार में शेयरों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

फेड मीटिंग का असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जनवरी में हुई बैठक से पता चलता है कि अधिकारी आगे की रणनीति को लेकर बंटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर महंगाई कम होती है तो राहत मिल सकती है, जबकि दूसरे मानते हैं कि अगर कीमतों का दबाव बना रहा तो सख्ती जारी रखनी पड़ेगी। ब्याज दरों में कटौती पर लंबे समय तक रोक या अमेरिकी फेड द्वारा फिर से दरें बढ़ाने से डॉलर मजबूत हो सकता है। इससे भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है। नकदी बाजार में लगातार सात महीनों की बिकवाली के बाद फरवरी में विदेशी निवेशकों की खरीदारी फिर से शुरू हुई है।

अमेरिका-ईरान तनाव पर बाजार की नजर

बुधवार को सीएनएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी सेना इस सप्ताहांत तक ईरान पर हमला करने की तैयारी में है। एक्सियोस ने बताया कि यह हमला छोटा नहीं बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा अभियान हो सकता है, जो लगभग युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। बाजार अमेरिका-ईरान संबंधों से जुड़े घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक हफ्ते के आखिरी में तनाव बढने की आशंका से अपनी पोजीशन घटा रहे हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी

कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी बाजार पर असर डाला है। पिछले सत्र में डब्ल्यूटीआई क्रूड फ्यूचर्स 4.60 प्रतिशत बढक़र 65.19 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 4.35 प्रतिशत बढक़र 70.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। गुरुवार को भी ब्रेंट क्रूड 70.53 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 65.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। ऊंची तेल कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये के लिए सही नहीं मानी जातीं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है।

मुकेश अंबानी की एआई में 10 लाख करोड़ निवेश करने की योजना

- भारत को सुलभ और व्यापक एआई युग में अग्रणी बनाना मुख्य उदेद्श्य

मुंबई ।

उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुरुवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में घोषणा की कि जियो और रिलायंस समूह अगले सात वर्षों में कृत्रिम मेधा (एआई) में 10 लाख करोड़ रुपये निवेश करेंगे। अंबानी ने स्पष्ट किया कि यह कोई सट्टा निवेश नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक, अनुशासित राष्ट्र निर्माण और मूल्य वृद्धि के लिए पूंजी है। अंबानी ने कहा कि एआई का सर्वश्रेष्ठ रूप अभी आना बाकी है और यह अपार समृद्धि का युग लाने की क्षमता रखता है। उन्होंने दुनिया के सामने दो रास्तों का जिक्र किया- एक तरफ दुर्लभ, महंगी और नियंत्रित एआई और दूसरी तरफ सस्ती एवं सभी के लिए सुलभ एआई। उनका उद्देश्य भारत को सुलभ और व्यापक एआई युग में अग्रणी बनाना है। मुकेश अंबानी ने बताया कि एआई में सबसे बड़ी बाधा प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग की उच्च लागत है। इसके समाधान के लिए जियो इंटेलिजेंस भारत का संप्रभु कंप्यूटिंग अवसंरचना तैयार करेगा, जिसमें गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर शामिल हैं। अंबानी ने जोर दिया कि जियो भारत को इंटरनेट युग से बुद्धिमता (एआई) युग में ले जाएगा। उनका लक्ष्य है कि हर नागरिक, हर क्षेत्र और सामाजिक विकास के हर पहलू तक एआई पहुंचाई जाए और वह भी विश्वसनीय, व्यापक और बेहद किफायती तरीके से।

1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड लेन-देन पर नए आयकर नियम

मुंबई । भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अब टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच चुका है। इस बीच आयकर विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जो 1962 के पुराने नियमों की जगह ले सकते हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का क्रेडिट कार्ड बिल गैर-नकद माध्यम से चुकाता है, तो बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को आयकर विभाग को रिपोर्ट करना होगा। वहीं 1 लाख रुपए या उससे अधिक का नकद भुगतान भी रिपोर्टिंग के दायरे में होगा। यह व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब और स्पष्ट और व्यवस्थित हो गई है। पैन कार्ड या अन्य दस्तावेज़ी प्रक्रिया में तीन महीने से अधिक पुराना न होने वाला क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अब एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे दस्तावेज़ों की सत्यता और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित होगी।

महाराष्ट्र सरकार मुक्तेश्वर में धारावी पुनर्विकास के लिए 118 एकड़ भूमि सौंपेगी

मुंबई ।

महाराष्ट्र सरकार ने मलाड-मालवानी के मुक्तेश्वर में स्थित 118 एकड़ भूमि धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) को सौंप दी है। यह भूमि उन धारावी निवासियों के लिए आवंटित की जाएगी जो पुनर्वास के पात्र हैं लेकिन धारावी में ही रहते हैं। अधिकारियों के अनुसार, यह मलाड की तीसरी सबसे बड़ी भूमि है, कुर्ला की मदर डेयरी और मुलुंड के जामास सॉल्टपैन के बाद। कुल 140 एकड़ भूमि में से 118 एकड़ सौंप दी गई है, जबकि 22 एकड़ अभी भी मुकदमेबाजी के अधीन हैं। परियोजना का कार्य स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएमडीपीएल) द्वारा किया जाएगा। भूमि का मालिकाना हक डीआरपी/एसआरए के पास रहेगा, जबकि एनएमडीपीएल को विकास अधिकार दिए जाएंगे। कुल भूमि का मूल्य लगभग 540 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें से 135 करोड़ रुपए पहले ही विकास अधिकार प्रीमियम के रूप में भुगतान किए जा चुके हैं। भूमि पर मुख्य रूप से ऊपरी मंजिल के निवासी और 1 जनवरी, 2011 के बाद और 15 नवंबर, 2022 से पहले धारावी में आने वाले लोग पुनर्वासित होंगे। इन निवासियों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आधुनिक और सुनियोजित टाउनशिप में स्थानांतरित किया जाएगा। परियोजना के अनुसार चरणबद्ध पुनर्वास किया जाएगा, ताकि लगभग सात वर्षों के भीतर सभी पात्र निवासियों को नए घर मिल सकें। डीआरपी के तहत कुल 540 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें कुर्ला, कंजूर, भांडुप, मुलुंड के नमक के मैदान और देवनार डंपिंग ग्राउंड के हिस्से शामिल हैं। अनुमान है कि परियोजना के तहत लगभग 10 लाख धारावी निवासियों के पुनर्वास के लिए 1.25-1.5 लाख नए घर बनाए जाएंगे।

आरबीआई ने बैंकों को अधिग्रहण के लिए कर्ज देने की अनुमति दी

- नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को अधिग्रहण के लिए कर्ज देने की अनुमति दी है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। यह क्षेत्र लंबे समय तक बैंकों के लिए बंद था, लेकिन अब कई सुरक्षा उपाय और शर्तों के साथ इसे खोला गया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बड़े अधिग्रहणों (अरबों डॉलर वाले) के लिए बैंक ऋण नहीं देंगे। एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ÷कोई पहले दिन से दौड़ने के बारे में नहीं सोच रहा। बैंक छोटे अवसरों से शुरुआत करेंगे और इसे 10-15 साल के अवसर के रूप में देखेंगे। अगले 3-5 वर्षों में कोई भी बैंक बहुत साहसिक कदम नहीं उठाएगा।÷ सरकारी बैंकरों ने भी कहा कि नियमों के तहत अधिकांश बैंक धीरे-धीरे मध्यम और बड़ी कंपनियों के साथ शुरुआत करेंगे।

ऋण की शर्तें और सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं-

- अधिग्रहण के लिए बैंक ऋण की सीमा अब *टियर-1 पूंजी का 20 फीसदी तक।
- कर्ज-इक्विटी अनुपात 3ः1 से अधिक नहीं।
- कर्ज लेने वाली कंपनी का न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये।
- कंपनी को लगातार तीन वर्षों तक शुद्ध लाभ होना चाहिए।
- असूचीबद्ध कंपनियों के लिए निवेश ग्रेड रेटिंग अनिवार्य।
- अधिग्रहण मूल्य का अधिकतम 75 फीसदी तक कर्ज, शेष 25 फीसदी के लिए ब्रिज फाइनेंस का विकल्प।

सरकारी बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि नियम छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अधिग्रहण को बढ़ावा देंगे। बैंकों को आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने और पहले कुछ सौदों में सावधानी रखने की आवश्यकता है।

सोने-चांदी की चमक से म्युचुअल फंड उद्योग में रिकॉर्ड बढ़त

म्युचुअल फंड निवेशकों की संख्या 18 महीने के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली । जनवरी में म्युचुअल फंड उद्योग में निवेशकों की संख्या में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। इस दौरान करीब 12 लाख नए निवेशक जुड़े, जिससे कुल फोलियो की संख्या बढ़कर 6.02 करोड़ हो गई। यह बढ़ोतरी पिछले 18 महीनों का उच्चतम स्तर है और वर्ष 2025 की औसत मासिक वृद्धि 5 लाख से दोगुने से भी अधिक है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेजी के पीछे सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी मुख्य कारण रही। निवेशकों ने कीमती धातुओं से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) और फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) में बढ़-चढ़कर निवेश किया। जनवरी में गोल्ड ईटीएफ ने शुद्ध निवेश और फोलियो वृद्धि के मामले में सक्रिय इक्विटी योजनाओं को पीछे छोड़ दिया। कुल फोलियो वृद्धि में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का योगदान 55 प्रतिशत रहा।

इसके अलावा, कीमती धातुओं से जुड़े एफओएफ में 33,503 करोड़ रुपये का संयुक्त निवेश हुआ, जो सक्रिय इक्विटी योजनाओं के शुद्ध निवेश से 40 प्रतिशत अधिक था। बाजार के जानकारों का कहना है कि गोल्ड स्कीमें उद्योग के लिए नए निवेशकों को जोड़ने का बड़ा माध्यम बन सकती हैं। भारत में सोने की सांस्कृतिक स्वीकृति इसे एक भरोसेमंद निवेश विकल्प बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की अस्थिरता के बीच सुरक्षित निवेश की तलाश और बेहतर रिटर्न की उम्मीद ने मौजूदा और नए दोनों तरह के निवेशकों को आकर्षित किया है। आने वाले महीनों में भी यह रुझान जारी रहने की संभावना है।

आईपीओ लिस्टिंग लाभ में वित्त वर्ष 2025-26 में गिरावट

- सिर्फ 65 फीसदी ऑफर ही इश्यू प्राइस से ऊपर खुले

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 में आईपीओ निवेशकों के लिए शुरुआती लाभ कम रहा। प्राइमडेटाबेस डॉट कॉम के आंकड़ों के अनुसार, इस वित्त वर्ष में जारी 99 आईपीओ में केवल 65 फीसदी ने अपनी निर्गम कीमत से अधिक पर लिस्टिंग की। तुलना करें तो वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 82.1 फीसदी था, जबकि वित्त वर्ष 2019 में न्यूनतम 42.9 फीसदी दर्ज किया गया था। सूचीबद्ध कीमत और शुरुआती कीमत के बीच औसत वृद्धि वित्त वर्ष 2026 में 4.1 फीसदी रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह 20.6 फीसदी थी।

पिछले सात वर्षों में अधिकांश वर्षों में दो अंकों में वृद्धि दर्ज की गई थी। कई आईपीओ में प्राइवेट इक्विटी फंड और अन्य संस्थागत निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। इसके कारण लिस्टिंग पर मुनाफ़ा सीमित हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती निवेशकों की बिक्री कीमतें इतनी थीं कि निवेशकों के लिए लाभ कम बचा।

विशेषज्ञों के अनुसार, निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि सभी आईपीओ लाभदायक नहीं होंगे।

लिस्टिंग पर तुरंत मुनाफा कमाने की रणनीति इस वित्त वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में जोखिम भरी रही।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 विश्वकप: जिम्बाब्वे की दूसरी बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब श्रीलंका को हराया

कोलंबो (एजेंसी)। जिम्बाब्वे ने ब्रायन बेनेट के नाबाद अर्धशतक की बदौलत आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट हराकर दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी। जिम्बाब्वे के स्पिनरों के खिलाफ धीमी पिच पर बीच के ओवरों में श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशानी आई लेकिन टी20 विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में बृहस्पतिवार को मेजबान टीम ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। इसके जवाब में जिम्बाब्वे ने सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए सिकंदर रजा के नेतृत्व में जीत हासिल की।

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरूआत अच्छी रही। सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा (22) और पाथुम निसांका (62) ने 4.5 ओवर में 54 रन बनाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज परेरा सहज नहीं दिखे लेकिन तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी को उन्होंने दो चौके लगाए। वह हालांकि मुजरबानी के बाउंसर पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट फाइन लेग पर ग्रीम क्रेमर को कैच दे बैठे। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पावरप्ले में एक विकेट पर 61 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद रनगति धीमी पड़ गई।

जिम्बाब्वे के स्पिनरों सिकंदर रजा, क्रेमर, रियान बर्ल और वेलिंगटन मसाकाजा ने मेजबान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अगले चार ओवरों में सिर्फ 21 रन बने। इस बीच कुसल मेंडिस का विकेट भी गिरा जो 20 गेंदों में 14 रन ही बना सके। वहीं पिछले मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बनाने वाले निसांका ने 34 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। वह क्रेमर की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने के प्रयास में टोनी मुनिनोगा को कैच दे बैठे। पवन रत्नायके ने 25 गेंद में 44 रन बनाये और ब्राड इवांस को 19वें ओवर में दो चौके और एक छक्का जड़कर श्रीलंका को 150 रन के पार पहुंचाया। आखिरी दो ओवरों में 30 रन बने।

टी20 विश्वकप: जिम्बाब्वे से हार के बाद श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका का पहला बयान आया सामने

कोलंबो (एजेंसी)। टी20 विश्व कप मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने कहा कि हमने जो स्कोर बनाया वह डिफेंड करने के लिए काफी अच्छा था। ब्रायन बेनेट के अर्धशतक और कप्तान सिकंदर रजा की 45 रन की पारियों के दम पर जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर अपराजेय रहते हुए ग्रुप की शीर्ष टीम के रूप में टी20 विश्व कप के सुपर आठ में प्रवेश किया। कठिन पिच पर जीत के लिए 179 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में चार विकेट पर 182 रन बनाए। बेनेट 48 गेंद में 63 और रजा 26 गेंद में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों टीमें ग्रुप बी से सुपर आठ में पहुंच चुकी है और लीग चरण में आस्ट्रेलिया को हराने वाली जिम्बाब्वे के प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है।

श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका ने कहा, 'हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही और सच कहूं तो, मुझे लगता है कि हमने जो स्कोर बनाया वह डिफेंड करने के लिए काफी अच्छा था। (मैच में) कुछ जगहें ऐसी थीं जहां हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे, लेकिन कुल मिलाकर मैं आज का स्कोर यही मानूंगा। मैं पथुम (निसांका) और पवन (रत्नायक) के खेलने के तरीके से बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि इस पिच पर (बैटिंग के हिसाब से) यह एक अच्छा टोटल था। प्लान हमेशा की तरह सिंपल था (बॉल से)। शुरुआत में विकेट लेना। बदकिस्मती से हम बॉल से वैसी शुरुआत नहीं कर पाए। नए खिलाड़ियों के आने से थोड़ी मुश्किल होती है, उन्हें भी सेट होने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन कोई बहाना नहीं। हम थोड़ा और बेहतर कर सकते थे।'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे कुछ फैसले थोड़े गैंबल जैसे भी थे। यह उन दिनों में से एक था जहां हम बॉल से बेहतर कर सकते थे, लेकिन फिर से, कोई बहाना नहीं। क्वालिफिकेशन हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हम जो भी मैच खेलते हैं, हम देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं। हां, हमने आज चमीरा को आराम दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई बहाना नहीं। हमने तीनों डिपार्टमेंट में ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि हमें मैदान पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। आज हममें इसी की कमी थी। उम्मीद है कि अगली बार जब हम मैदान पर उतरेंगे तो बेहतर एटीट्यूड के साथ वापस आएंगे।'

टी20 विश्व कप : होप और जोसेफ के अच्छे प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने इटली को 42 रनों से हराया

कोलकाता (एजेंसी)। कप्तान शाई होप और तेज गेंदबाज शामार जोसेफ के अच्छे प्रदर्शन से वेस्टइंडीज ने गुरुवार को यहां टी20 विश्व कप क्रिकेट के अपने अंतिम लीग मुकाबले में इटली को 42 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप सी में नंबर एक पर बनी हुई है। वेस्टइंडीज ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए होप के 46 75 रनों की सहायता से 20 ओवरों में छह विकेट पर 165 रन बनाये। आज के खेल का आकर्षण होप की पारी रही। होप ने तेजी से खेलते हुए 28 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया पर अन्य बल्लेबाजों का उन्हें साथ नहीं मिला, इस कारण टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पायी। इसके बाद जीत के लिए मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की टीम 18 ओवर में 123 रन ही बना पायी। वेस्टइंडीज की ओर से शामार जोसेफ ने 30 रन देकर चार विकेट लिए। इसके इसके अलावा चार कैच भी पकड़े। वहीं इस मैच के साथ ही इटली का अभियान इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है। इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसन नहीं था। रोस्टन चेज 25 गेंद पर 24, शेरफेन रदरफोर्ड 15 गेंद पर नाबाद 24 रन और मैथ्यू फोर्डे आठ गेंद पर नाबाद 16 रन ही बना पाये। इटली के गेंदबाजों ने इंडीज बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। बेन मनेंटी और और कृशान कालुगामगे ने दो-दो विकेट लेकर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाये रखा। केव ग्रांट स्टीवर्ट के ही एक ओवर में 19 रन बने। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए इटली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वह पावर प्ले में तीन विकेट पर 37 रन ही बना पायी। एंथनी मोस्का ने 19 रन बनाये। वहीं उनके भाई जस्टिन मोस्का 02 रन ही बना पाये। सैयद नकवी भी 6 रन ही बना पाये। जेजे स्मट्स ने 27 गेंद में 24 रन जबकि कप्तान हैरी मैनेंटी ने 8 रन बनाये। इटली की आधी टीम 78 रनों पर ही आउट हो गयी। इसके बाद बेन मैनेंटी ने इटली को 100 रनों तक पहुंचाया। वहीं ग्रांट स्टीवर्ट 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गये।

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 में भारतीय टीम को हराया

1-1 से सीरीज बराबरी पर पहुंची

कैनबरा (एजेंसी)। मेजबान ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने यहां खेले गये दूसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 19 रनों से हराकर तीन मैच की सीरीज में 1-1 से वापसी की है। ऑस्ट्रेलिय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जॉर्जिया वोल के अर्धशतक 88 रनों और बेथ मूनी के 46 रनों की सहायता से 5 विकेट पर 163 रन बनाए। इसके बाद जीत के लिए मिले 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नौ विकेट पर 144 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी ढ़ह गयी। कप्तान हरमनप्रीत कौर 36, स्मृति मंधाना 31 और शेफाली वर्मा 29 के अलावा अन्य बल्लेबाज असफल रहीं।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से एश्ले गार्डनर ने 22 रन देकर तीन विकेट जबकि किम गार्थ, अनाबेल सदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिनू ने दो-दो विकेट लिए। । भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही थी और उसने नौवें ओवर में एक विकेट पर 65 रन बना लिए थे पर इसके बाद टीम ने अंत में सात रन के अंदर ही छह विकेट खो दिये। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पावरप्ले में ही 54 रन बना लिए थे पर इसके बाद शेफाली के आउट होने से बल्लेबाजी ढ़हनी शुरु हो गयी। जेमिमा रोड्रिग्स भी 4 रन ही बना पायी। मंधाना के रूप में तीसरा विकेट गिरा। भारतीय टीम ने तीन विकेट पर 71 रन बना लिए थे। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत और ऋचा घोष 19 ने चौथे विकेट के लिए 55 रन बनाये। बाद में तेजी से रन बनाने के प्रयास में विकेट एक के बाद एक गिरते गये। हरमनप्रीत को 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर गार्थ ने पेवेलियन भेजा। इसके बाद ऋचा भी गार्डनर की गेंद पर स्टंप आउट हो गईं। 18वें ओवर में गार्डनर ने दीप्ति शर्मा को सदरलैंड के हाथों कैच कराया। इसके बाद भारतीय पारी सिमट गयी।

हरमनप्रीत सबसे अधिक अंतराष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनीं, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का रिकार्ड टूटा

कैनबरा । भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां दूसरे टी20 क्रिकेट मैच के लिए मैदान में उतरते ही एक रिकार्ड बना दिया है । अब हरमनप्रीत महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं । हरमनप्रीत ने यहां मैदान पर उतरने के साथ ही अपना 356 वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और वह न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स से आगे निकल गयी हैं । । बेट्स ने 355 मैच खेले हैं । वहीं सबसे अधिक मैच खेलने के मामले में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी हैं । पेरी के नाम पर 349 मैच हैं । वहीं भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने 333 मैच खेले हैं, जबकि शार्लोट एडवर्ड्स ने इंग्लैंड के लिए 309 मैच खेले हैं । महिला क्रिकेट में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड सोफी डिवाइन के नाम 305, इंग्लैंड की हीथर नाइट के नाम 303 और डैनी व्याट-हॉज के नाम 302 मैच हैं । हरमनप्रीत ने अपने क्रिकेट करियर में अब तक छह टेस्ट, 161 एकदिवसीय और 189 टी20 मैच खेले हैं । छह टेस्ट मैचों में उनके नाम 200 रन जबकि एकदिवसीय में 4,409 और टी20 मैचों में 3,784 रन हैं । हरमनप्रीत ने सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनने पर खुशी जताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य के लिए आगे भी अच्छा प्रदर्शन करना रहेगा ।

बांग्लादेश के नये खेलमंत्री अमीनुल बोले, भारत और बीसीसीआई से बेहतर संबंध चाहते हैं

ढाका । बांग्लादेश सरकार के नये खेल मंत्री अमीनुल हक ने कहा है कि वह भारत के साथ ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से भी बेहतर बनाना चाहता है । खेल मंत्री की शपथ लेने के बाद हक ने कहा कि वह बीसीसीआई से संबंधों को फिर से पहले की तरह बनाना चाहते हैं । साथ ही कहा कि हाल में कुछ मामलों को लेकर दोनो ही देशों के बीच दूरियां बढ़ी हैं । उन्होंने कहा, शपथ लेने के बाद मैंने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुकाकात कर उनसे टी20 विश्व कप में भाग नहीं लेने के बाद के हालातों पर भी बात की जो सकारात्मक रही । मैंने उनसे कहा कि हम इस मामले को बातचीत से हल करना चाहते हैं । हम सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं । हक ने कहा, खेल के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं । कुछ बाधाओं के कारण, हम टी20 विश्व कप नहीं खेल सके । बातचीत के दौरान इस प्रकार के मामलों को हाल किया जाता तो आज हमारी टीम भी विश्वकप में खेल रही होती । गौरतलब है कि बांग्लादेश की पिछली सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत में टीम भेजने से इंकार करते हुए कहा था कि उनके मैच श्रीलंका में रखे जाएं पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड (आईसीसी) ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था । जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार से बात करने के बाद खेल से बाहर होने का फैसला किया था ।

सुपर-8 मुकाबलों के लिए करने होंगे सुधार : सूर्यकुमार

अहमदाबाद । भारतीय क्रिकेट टीम को नीदरलैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप क्रिकेट के अपने अंतिम मुकाबले में 17 रनों से जीत मिली पर कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे संतुष्ट नहीं हैं । सूर्यकुमार का कहना है कि सुपर-8 से पहले सब कुछ सही है ये नहीं कहा जा सकता । टीम को अभी कुछ सुधार भी करने हैं । इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए । वहीं इसके बाद एसोसिएट इच टीम ने भी सात विकेट पर 176 रन बनाये । इसी को देखते हुए कप्तान ने कहा कि जीत में भी सीख मिलती है, हमें और कसी गेंदबाजी करनी चाहिये थी । उन्होंने कहा कि पूरी तरह गेंदबाजों को भी दोष नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ओसा काफी अधिक थी । जिससे भी गेंदबाजों को परेशानी हुई । उन्होंने सुपर आठ को लेकर कहा, 'शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है पर सभी बल्लेबाजों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और बीच के ओवरों में विकेट कैसा बर्ताव कर सकता है । इसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी हैं, जो मैच को अच्छी तरह समाप्त कर सकते हैं ।' सुपर-8 को लेकर पूछे एक सवाल पर उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ पूरी तरह से सही था । जीत में भी कई प्रकार की सीख मिलती है और हमने कुछ चीजें सीखी हैं । अब हम आगे के मैचों को लेकर विचार-विमर्श करेंगे ।'

'शिवम दुबे को बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है', दिग्गज खिलाड़ी ने की भारतीय ऑलराउंडर की तारीफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिवम दुबे के बल्ले और गेंद दोनों से ऑल-राउंड प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अहमदाबाद में नीदरलैंड्स को 17 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में टॉप कर रहे। स्टार स्पोर्ट्स के 'क्रिकेट लाइव' प्रोग्राम में बोलते हुए जियोस्टार एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने दुबे के बेहतर शॉट सिलेक्शन, वरुण चक्रवर्ती के अहम स्पेल की तारीफ की और टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म पर अपने विचार शेयर किए।

गावस्कर ने उस एक शॉट की ओर इशारा किया जो शिवम दुबे के खेल को दूसरे लेवल पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा, 'शिवम दुबे को बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास कई तरह के शॉट हैं। आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उनमें लॉन्ग ऑन के ऊपर से हिट करने की पावर भी है। वह सिर्फ मिड-विकेट और स्क्वायर-लेग के ऊपर से हिट करने की कोशिश नहीं करते। वह लॉन्ग ऑफ को भी क्लियर कर सकते हैं। अगर वह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड-आउट शॉट डेवलप करने पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो वह सच में एक खतरनाक बैट्समैन बन जाएंगे।'

उन्होंने कहा, 'फिर वह बॉल को ग्राउंड के किसी भी हिस्से में हिट कर सकते हैं। जिस तरह से शिवम दुबे हर इनिंग के साथ मैच्योर हो रहे हैं, वह इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है।' मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के शानदार रन पर उन्होंने कहा, 'वरुण चक्रवर्ती के चार ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लेना कमाल का है। जब आप विकेट लेते हैं, तो आप विरोधी टीम के रन भी छीन लेते हैं। साफ है, वरुण आपके की बॉलर होंगे। इंडिया काफी हद तक वरुण के 4 ओवर पर डिपेंड करेगा। सुपर 8 स्टेज में विरोधी टीम उनका मुकाबला कैसे करती है, यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।'

सबसे छोटे फॉर्मेट के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा अभी तक टूर्नामेंट में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट की तीन इनिंग्स में एक भी रन नहीं बनाया है। अभिषेक शर्मा के स्ट्रगल पर गावस्कर ने कहा, 'अभिषेक शर्मा एक अच्छा लड़का है, लेकिन उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही हैं। अगर उसने USA के खिलाफ अच्छी शुरुआत की होती, तो बात अलग होती। अब बड़े छक्के मारने वाला और टॉप बैटर होने का प्रेशर दिख रहा है। अपनी शॉट रेंज के साथ उसे बीच में समय बिताने की जरूरत है। वह अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पर बाउंड्री या सिक्स मारने की कोशिश नहीं कर सकता।'

उन्होंने कहा, 'अगर बड़े शॉट लगते हैं, तो ठीक है। लेकिन उसे खुद को लाइन के पार बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। एक सिंगल लो और रन बना लो। चार

डॉट बॉल भी मायने नहीं रखतीं। वह बाद में उनकी भरपाई कर सकता है। उसे शुरुआत में स्मार्ट खेलने की जरूरत है। एक या दो ओवर जमने में बिताओ, फिर अपना नैचुरल गेम खेलो। पहले, बस रन बनाओ। हर बैटर पहला रन चाहता है। एक बार जब वह इसे बना लेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

तीन मैच पॉइंट बचा कर गॉफ क्वार्टर फाइनल में पहुंची

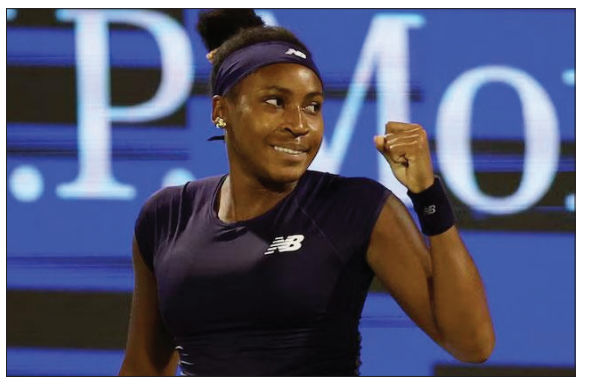

दुबई । कोको गॉफ ने बुधवार रात को तीन मैच पॉइंट बचाए और एलिस मर्टेंस को 2-6, 7-6 (9), 6-3 से हराकर दुबई क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं । 2 घंटे और 18 मिनट में मिली इस जीत ने 2021 के बाद पहली बार यह दिखाया कि गॉफ ने टूर-लेवल की जीत में मैच पॉइंट बचाए और बेल्जियम की खिलाड़ी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 5-0 कर लिया । गॉफ ने कोर्ट पर अपने इंटरव्यू में कहा, 'पूरा मैच ऐसा लगा जैसे मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है ।यह सबसे अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने बस इसमें बने रहने की कोशिश की, और मैंने हर पॉइंट के लिए लड़ाई की । मुझे खुशी है कि मैं आज रिजल्ट ला पाई ।' गॉफ 2001 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में चार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गईं । वह 2009 में इस फॉर्मेट के शुरू होने के बाद से 100 डब्ल्यूटीए 1000 मेन-ड्रॉ जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी हैं । गॉफ का अगला मुकाबला एलेक्जेंड्रा एला से होगा ताकि वह नंबर 101 जीत हासिल कर सकें और अपने दूसरे दुबई सेमीफाइनल में पहुंच सकें । यह ड्रॉ लेवल पर उनके बीच पहली मुलाकात होगी ।

टी20 विश्वकप से शुरुआत में बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक दावेदारी को भी झटका

मुम्बई । आईसीसी टी20 विश्वकप से बाहर होने से ऑस्ट्रेलियाई टीम की लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक की दावेदारी भी कमजोर पड़ी है । ओलंपिक में पुरुषों की टी20 प्रतियोगिता में केवल छह टीमों को ही अवसर मिलेगा । इसमें अंतिम चयन कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन सिस्टम व आईसीसी रैंकिंग के आधार पर होगा । विश्व कप से बाहर होने से वह रैंकिंग में न्यूज़ीलैंड से पिछड़ रही है । ऐसे में उसकी जगह कीवी टीम को मिल सकती है । ऐसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप स्तर से ही बाहर होने से न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम की राह आसान हो गयी है । ऐसे में अब अगर कीवी टीम सेमीफाइनल या उससे आगे तक पहुंचती है, तो रैंकिंग में वह ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पहुंच जाएगी । इससे उससे ओलंपिक के लिए प्रवेश मिल सकता है । कीवी टीम का आईसीसी इवेंट्स में रिकॉर्ड अच्छा रहा है, वे कई बार नॉकआउट चरण तक पहुंचे हैं जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत होती है । ऐसे में यदि रैंकिंग में न्यूज़ीलैंड आगे निकल जाता है, तो कंगारुओं को को अंतिम ओलंपिक स्लॉट के लिए दूसरी रैंक वाली टीमों के साथ अलग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेलना पड़ सकता है जो उसकी प्रतिष्ठा के लिए झटका होगा । इसके अलावा इस क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में अगर वह शीर्ष पर रहती है तो भी उसे ओलंपिक में प्रवेश मिलेगा इसकी गारंटी नहीं रहेगी ।

अभिषेक पर भड़के प्रशंसक, बोले इससे तो अधिक रन सैमसन बना रहे थे

अहमदाबाद । भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खराब दौर समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है । अभिषेक टी20 विश्वकप में अपने तीसरे मैच में भी खाता नहीं खो पाये । इससे प्रशंसक उनपर भड़क गये हैं । प्रशंसकों का कहना है कि संजू सैमसन के भी उनसे अधिक रन हैं । सैमसन को अपनी खराब फार्म के कारण ही अभिषेक की वापसी के बाद बाहर किया किया गया है पर जिस

प्रकार से अभिषेक रन बनाने में विफल हुए हैं । उससे ये बदलाव कारगर साबित नहीं हुआ है । प्रशंसकों को उम्मीद थी कि अभिषेक आक्रामक अंदाज में खेलेंगे पर जब तीसरे मुकाबले में भी ऐसा नहीं हुआ तो उनके सब्र का बांध टूट गया । जिस तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद प्रशंसकों को थी । वह अब भी नहीं दिखी । इसके बाद सोशल मीडिया पर अभिषेक की जमकर खिंचाई हुई । प्रशंसकों ने तंज कसा कि इससे तो अधिक रन सैमसन के हैं । वहीं कुछ प्रशंसकों का मानना है कि सुपर-8 के लिए सैमसन को टीम में शामिल किया जाना चाहिये । सैमसन को अभिषेक के बीमार होने के कारण एक मैच में अवसर मिला था । उस मुकाबले में सैमसन ने 22 रन बनाए थे । अभिषेक का यह पहला ही टी20 विव कप है और उनसे इस तरह के प्रदर्शन की प्रशंसकों को उम्मीद नहीं थी । वह पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ विफल रहे । वहीं बीमार होने के कारण नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाए । पाकिस्तान के खिलाफ उनसे बड़े स्कोर की उम्मीथ थी पर वह असफल रहे । नीदरलैंड के खिलाफ मैच में भी उनका खाता नहीं हुआ । अब अगर वह सुपर-8 में रन नहीं बनाते तो टीम में उनकी जगह खतरे में आ जाएगी ।

'बहुत शुक्रगुजार हूं', न्यूजीलैंड की लॉरेन डाउन ने संन्यास का किया ऐलान

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड) (एजेंसी)। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर लॉरेन डाउन ने गुरुवार को क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 30 साल की बैटर ने 4 मार्च 2018 को लिंकन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच में न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया था। दाएं हाथ की बल्लेबाज ने 9 फरवरी 2020 को वेलिंगटन में साउथ अफ्रीका विमेन के खिलाफ अपना टी20आई डेब्यू किया था। उन्होंने अपना आखिरी ODI मैच 23 दिसंबर 2024 को वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए टी20आई में अपना आखिरी मैच 7 दिसंबर 2022 को क्रीन्सटाउन में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से जारी एक बयान में डाउन ने कहा, 'मुझे व्हाइट फर्न्स ग्रुप का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लड़कियों के साथ रहना याद आएगा, लेकिन अब मैं साइडलाइन से देखने और यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यह ग्रुप क्या हासिल कर पाता है।' लॉरेन डाउन ने 35 ODI और 31 इनिंग खेलीं जिसमें उन्होंने 62.06 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बनाए। दाएं हाथ की बैट्समैन ने तीन हाफ-सेंचुरी लगाईं। टी20आई में 30 साल की इस खिलाड़ी ने 13 मैच और 9 इनिंग में 86.11 के स्ट्राइक रेट से 93 रन बनाए।

डाउन ने कहा, 'मेरे क्रिकेट करियर का एक बड़ा हिस्सा ऑकलैंड सेटअप में रहा है और मैं ऑकलैंड क्रिकेट, अपने कोच और टीम के साथियों को मेरे सफर में उनके रोल के लिए जितना धन्यवाद दूं कम है।' डाउन पांच सफल हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड कैपेन का हिस्सा थीं जिसमें उन्होंने ऑकलैंड हाट्र्स को 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2017-18 और हाल ही में 2019-20 में महिलाओं का 50 ओवर का टाइटल जीतने में मदद की, जहां उन्होंने हैमिल्टन के सेडन पार्क में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को 67 रन से हराने में मदद करने के लिए ग्रैंड फाइनल में 90 रन बनाए।

डाउन ने अपने करियर का अंत हाट्र्स की तीसरी सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाली (1,496 रन) और चौथी सबसे ज्यादा लिस्ट, रन बनाने वाली (2,690 रन) खिलाड़ी के तौर पर भी किया और एक ऑलराउंडर के तौर पर अपने शुरुआती दिनों में 41 विकेट लिए। अंगूठे की चोट की वजह से डाउन न्यूजीलैंड में 2022 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाईं और उसी साल बाद में बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नहीं खेल पाईं, लेकिन सितंबर 2022 में वेस्ट इंडीज टूर के लिए टीम में वापस आ गईं और साउथ अफ्रीका में 2023 आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए बेन सॉयर की टीम में शामिल हो गईं।

डाउन ने अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए 2023-24 सीजन के लिए व्हाइट फर्न्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने का ऑप्शन चुना, फिर 2024-25 लिस्ट में वापस आ गईं और 2024 में इंग्लैंड और भारत के टूर पर शामिल हुईं। उन्होंने पिछली गर्मियों में सेलो बेसिन रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI में व्हाइट फर्न्स को आखिरी बार रिप्रेजेंट किया।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

कोलोराडो हाइवे पर 30 से अधिक वाहनों की टक्कर, 4 लोगों की मौत

कोलोराडो, एजेंसी। अधिकारियों ने बताया कि कोलोराडो में मंगलवार को एक अंतरराज्यीय राजमार्ग पर धूल भरी आंधी के कारण चालकों को देखने में कठिनाई होने से छह सेमीट्रेलरों सहित 30 से अधिक वाहनों की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। कोलोराडो स्टेट पेट्रोल ने बताया कि तेज हवाओं से उड़ी धूल के कारण सुबह करीब 10 बजे प्यूब्लो के दक्षिण में इंटरस्टेट 25 पर हुए हादसे के समय स्थिति 'धुंधली' हो गई थी। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को 'बहुत कम या बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था'। पुलिस ने बताया कि 29 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोटों की गंभीरता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। दुर्घटना के कारणों की अभी भी जांच चल रही है। गश्ती दल की प्रवक्ता शेरी मेंडेज ने बताया कि कम दृश्यता को दुर्घटना के एक कारण के रूप में माना जाएगा, लेकिन अन्य कारण भी हो सकते हैं। मंगलवार को कोलोराडो के पूर्वी हिस्से में तेज हवाएं चल रही थीं, जो गर्म मौसम और अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों के साथ मिलकर जंगल की आग के खतरे को भी बढ़ा रही हैं और डेनवर के हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी का कारण बन रही हैं।

अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर ड्रग्स से भरी तीन नावों पर किए हमले, 11 लोगों की मौत

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को कहा कि उसने तीसरे अमेरिकी जलक्षेत्र में ड्रग्स की तस्करी के आरोपी तीन नावों पर हमले किए, जिसमें 11 लोग मारे गए। यह ट्रंप प्रशासन के महीनों से चल रहे अभियान के सबसे घातक दिनों में से एक था। सोमवार को किए गए सिलसिलेवार हमलों के बाद मरने वालों की संख्या कम से कम 145 हो गई है, जब से प्रशासन ने सितंबर की शुरुआत से छोटे जहाजों में उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है जिन्हें वह नारकोटेररिस्ट कहता है। 42 ज्ञात हमलों पर सेना के अधिकांश बयानों की तरह, अमेरिकी दक्षिणी कमान ने कहा कि उसने ज्ञात तस्करी मार्गों पर कथित मादक पदार्थों के तस्करों को निशाना बनाया। उसने कहा कि पूर्वी प्रशांत महासागर में चार-चार लोगों को ले जा रहे दो जहाजों पर हमला किया गया, जबकि कैरेबियन सागर में तीन लोगों को ले जा रहे एक तीसरे जहाज पर हमला किया गया। सेना ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि ये जहाज ड्रग्स की ढुलाई कर रहे थे, लेकिन उसने ऐसे वीडियो पोस्ट किए जिनमें नौकाओं को नष्ट होते हुए दिखाया गया था।

एपस्टीन कनेक्शन : हयात होटल के चेयरमैन थॉमस प्रिट्जकर ने दिया इस्तीफा

न्यूयार्क, एजेंसी। अमेरिका के न्याय विभाग (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) की ओर से जारी नई फाइलों में दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से करीबी संपर्क सामने आने के बाद अरबपति कारोबारी थॉमस प्रिट्जकर ने वैश्विक होटल श्रृंखला हयात होटल के चेयरमैन पद से हटने की घोषणा की है। प्रिट्जकर ने स्वीकार किया कि एप्स्टीन से संपर्क बनाए रखना भयानक निर्णय था। बीबीसी के अनुसार, हाल में सार्वजनिक फाइलों से पता चला कि प्रिट्जकर 2008 में एपस्टीन के यौन अपराधों में दोष स्वीकार करने के बाद भी कई वर्ष उसके संपर्क में थे। प्रिट्जकर ने कहा कि उन्होंने एपस्टीन से दूरी बनाने में देर कर गंभीर गलती की। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी हयात को सही दिशा में आगे बढ़ाने की है।

ब्रिटेन और भारत में एमपॉक्स की पहचान, दो अलग-अलग क्लेड से मिलकर बना वायरस

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन और भारत में एमपॉक्स वायरस के एक नए बदले हुए स्वरूप की पहचान हुई है, जिसे वैज्ञानिक रिकॉम्बिनेंट वायरस कह रहे हैं। यह नया रूप वायरस के दो अलग-अलग प्रकार क्लेड आईबी और क्लेड आईआईबी के आपस में मिल जाने से बना है। अब तक ऐसे दो ही मामले सामने आए हैं और दोनों मरीज स्वस्थ हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि फिलहाल आम जनता के लिए जोखिम कम है, हालांकि उच्च जोखिम समूहों में सतर्कता जरूरी बनी हुई है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह एक संक्रामक बीमारी है, जो एमपॉक्स वायरस से होती है। एमपॉक्स वायरस के दो मुख्य क्लेड माने जाते हैं, क्लेड आई और क्लेड आईआई। क्लेड आई के भीतर आईए और आईबी उपसमूह आते हैं, जबकि क्लेड आईआई में आईआईए और आईआईबी शामिल हैं। हाल का वैश्विक प्रकोप मुख्य रूप से क्लेड आईआईबी से जुड़ा रहा है। अब जो नया रीकॉम्बिनेंट मामला सामने आया है, उसमें क्लेड आईबी और क्लेड आईआईबी दोनों के जीन पाए गए हैं। भारत में पाया गया यह केस दुनिया में इस नए रीकॉम्बिनेंट एमपॉक्स वायरस का सबसे शुरुआती ज्ञात मामला माना जा रहा है।

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 'तोहफे' में दिए उसी के तीन सैनिक, कई महीनों पहले किया था कैद

काबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान सरकार ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने पिछले साल अक्टूबर में सीमा पार लड़ाई के दौरान पकड़े गए तीन पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। यह कदम रमजान के पवित्र महीने के मद्देनजर उठाया गया है। सऊदी अरब की मध्यस्थताः अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में बताया कि इन सैनिकों को सोमवार को काबुल आए एक सऊदी प्रतिनिधिमंडल को सौंप दिया गया। यह प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा था।

गिरफ्तारी का समयः मुजाहिद के अनुसार, इन तीन सैनिकों को 12 अक्टूबर को हुई लड़ाई के दौरान बंदी बनाया गया था।

रिहाई का कारणः उन्होंने कहा कि सैनिकों को रिहा करने का निर्णय रमजान की शुरुआत को देखते हुए लिया गया है, जो इस्लाम में उपवास और आत्म-चिंतन का पवित्र महीना माना जाता है। अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी पाकिस्तान के बीच पिछले साल अक्टूबर से ही तनाव काफी बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव की कहानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में जो तल्खी दिखाई दे रही है, उसकी जड़ें पिछले साल अक्टूबर की घटनाओं में छिपी हैं। भले ही अब 3 सैनिकों की रिहाई को एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्तों की डोर बेहद कमजोर हो चुकी है।

विवाद की चिंगारी: 9 अक्टूबर का काबुल धमाका : इस पूरे तनाव की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई, जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई जोरदार धमाके हुए। इन धमाकों ने पूरे शहर को दहला दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तुरंत इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। अफगान सरकार ने न केवल पाकिस्तान पर आरोप लगाए, बल्कि इन हमलों का बदला लेने की कसम भी खाई।

बदले की आग और सीमा पर युद्ध : काबुल धमाकों के ठीक बाद, प्रतिशोध की भावना ने दोनों देशों की सीमाओं पर युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। तालिबान के 'बदला लेने' के बयान के बाद सीमा पर भीषण गोलाबारी शुरू हो गई।

12 अक्टूबर का दिनः लड़ाई के दौरान 12 अक्टूबर का दिन सबसे महत्वपूर्ण रहा, जब अफगान बलों ने लड़ाई के दौरान तीन पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया (जिन्हें अब रिहा किया गया है)। यह संघर्ष इतना घातक था कि इसमें दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक, आम नागरिक और संदिग्ध उग्रवादी मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए।

हाल के वर्षों का सबसे भीषण संघर्ष : रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्टूबर में हुई यह लड़ाई पिछले कई वर्षों में दोनों पड़ोसियों के बीच हुई सबसे भीषण लड़ाई थी। इसने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया।

शांति की कोशिशें और नाकामी जब हालात बेकाबू होने लगे, तो खाड़ी देशों ने हस्तक्षेप कियाः कतर की मध्यस्थताः कतर ने दोनों देशों के बीच बीच-बचाव किया, जिसके बाद एक 'युद्धविराम' लागू हुआ। इससे सीमा पर तोपें तो शांत हो गईं, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। इस्तांबुल वार्ता की विफलताः युद्धविराम के बाद, तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता आयोजित की गई ताकि कोई स्थाई समाधान निकल सके। लेकिन, यह बातचीत किसी ठोस समझौते या नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।

वर्तमान राजनयिक स्थिति : हालात को सुधारने के लिए कतर की मध्यस्थता में एक युद्धविराम समझौता हुआ था, जिससे तनाव में कुछ कमी आई है। हालांकि, इस्तांबुल में हुई बाद की शांति वार्ता किसी ठोस समझौते पर पहुंचने में विफल रही, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल, इन तीन सैनिकों की रिहाई पर पाकिस्तान की ओर से कोई तत्काल टिप्पणी नहीं आई है।

अमेरिकी संसद भवन की तरफ हथियार लेकर दौड़ा 18 वर्ष का किशोर, सुरक्षाबलों ने किया गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी संसद भवन (यूएस कैपिटल) की सुरक्षा में उस समय हलचल मच गई जब एक 18 वर्षीय युवक लोडेड शॉटगन के साथ इमारत की ओर बढ़ता हुआ पाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पुलिस (स्ट्रक) ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया। त्वरित कार्रवाई के चलते घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान जॉर्जिया के स्मिर्ना निवासी कार्टर कामाचो के रूप में हुई है। वह मंगलवार दोपहर कैपिटल के लोअर वेस्ट टेरेस की दिशा में हथियार लेकर जा रहा था, तभी ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। अधिकारियों ने उसे रोकते हुए हथियार नीचे रखने और जमीन पर लेटने का आदेश दिया, जिसका उसने पालन किया और उसे बिना किसी प्रतिरोध के हिरासत में ले लिया गया। कैपिटल पुलिस प्रमुख माइकल सुलिवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी कैपिटल की सीढ़ियों के आधार तक पहुंच गया था, इससे पहले कि उसे पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान अधिकारियों ने एहतियातन अपने हथियार भी निकाल लिए थे।

आरोपी के पास से क्या-क्या हुआ बरामद : जांच में पता चला कि आरोपी एक सफेद मर्सिडीज-बेंज एसयूवी से मैरीलैंड एवेन्यू साउथवेस्ट के 100 ब्लॉक तक आया था और वहीं से शॉटगन लेकर बाहर निकला। वाहन से केव्लर हेलमेट, गैस मास्क और अतिरिक्त गोला-बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने यह भी बताया कि वाहन आरोपी के नाम पर पंजीकृत नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध टैक्टिकल वेस्ट और टैक्टिकल ग्लव्स पहने हुए था और उसके पास कई राउंड गोलियां भी थीं। उसे गैरकानूनी गतिविधियों, बिना लाइसेंस राइफल रखने, अपंजीकृत हथियार और अपंजीकृत गोला-बारूद रखने जैसे आरोपों में चार्ज किया गया है। फिलहाल कैपिटल पुलिस की थ्रेट असेसमेंट यूनिट उसके मकसद की जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में यातायात अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया और लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नियमित सुरक्षा अभ्यास और एक्टिव थ्रेट ड्रिल्स की वजह से पुलिस की प्रतिक्रिया तेज और प्रभावी रही। वहीं, पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस घटना का आगामी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

अमेरिका-ईरान बातचीत में तनाव, जेडी वेंस बोले-राष्ट्रपति ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं तेहरान

जिनेवा, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर ताजा बयान सामने आया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तय की गई मुख्य शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि जिनेवा में हुई बातचीत 'कुछ मायनों में ठीक रही', क्योंकि दोनों देशों ने आगे भी बैठक जारी रखने पर सहमति जताई है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने अब तक ट्रंप की प्रमुख शर्तों को स्वीकार नहीं किया है। उनके मुताबिक- राष्ट्रपति ट्रंप ने कूटनीतिक समाधान के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान अभी इन शर्तों पर खुलकर सहमति देने को तैयार नहीं दिख रहा। जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका अभी भी बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत बेनतीजा रही, तो आगे क्या करना है- इसका फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। उनका कहना था, 'हम चाहते हैं कि मामला बातचीत से सुलझे, लेकिन अगर कूटनीति की सीमा खत्म हो जाती है, तो अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा।' अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाए। वहीं ईरान अपने अधिकारों और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में बातचीत का दूसरा दौर खत्म हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, यह बैठक लगभग तीन घंटे तक चली, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला है। मंगलवार को हुई यह मुलाकात परमाणु मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत थी। जिनेवा में वार्ता व अभ्यास ऐसे समय हुए जब अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है।

अफगानिस्तान में घरेलू हिंसा को मिल गया कानूनी लाइसेंस

काबुल, एजेंसी। अफगानिस्तान में महिलाओं की दयनीय हालत छिपी नहीं है। 2021 में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से यहां महिलाओं के अधिकारों का लगातार दोहन हुआ है। तालिबानी हुकूमत ने देश में महिलाओं के पढ़ने, लिखने, बाहर जाने, यहां तक कि सार्वजनिक जगहों पर हंसने तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच अब अफगानिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को भी कानूनी लाइसेंस दे दिया गया है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने हाल ही में 90 पन्नों वाली नई दंड संहिता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कानून महिलाओं के लिए सजा से कम नहीं है।

नए नियमों को आधिकारिक रूप से 'दे महाकुमु जजाई उसूलनामा' का नाम दिया गया है। तालिबान सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए जाने वाले इस कानून के तहत सजा की प्रकृति इस आधार पर तय की जाएगी कि पीड़ित व्यक्ति 'आजाद' है या 'गुलाम'। इस व्यवस्था में समाज को ऊंचे और निचले दर्जे में बांटने की बात कही गई है। ऊपरी श्रेणी में धार्मिक नेता और मुल्ला शामिल होंगे, जबकि निचली श्रेणी के लोगों पर शारीरिक दंड को अधिक स्वीकार्य माना गया है। इसमें महिलाओं को व्यवहारिक रूप से 'गुलाम' की श्रेणी में रखा गया है और पति को 'स्वामी' का दर्जा दिया गया है। नए नियमों के तहत गंभीर अपराधों की सुनवाई इस्लामी मौलवियों द्वारा की जाएगी। कम गंभीर मामलों में 'ताज़ीर' नाम की वैकल्पिक सजा लागू होगी, जिसके तहत पति अपनी पत्नी को दंड दे सकता है। हालांकि पत्नी पर शारीरिक हिंसा के मामलों में न्याय की स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी गई है। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत करना चाहती है, तो उसे धार्मिक जज के सामने गंभीर शारीरिक चोट का सबूत पेश करना होगा। साथ ही उसे पूरी तरह ढका हुआ पहनावा पहनना होगा और एक पुरुष संरक्षक की मौजूदगी जरूरी होगी, जो अधिकतर मामलों में उसका पति ही होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर कोई महिला अपने साथ हुई गंभीर हिंसा साबित भी कर दे, तो आरोपी को न्यूनतम 15 दिन की जेल ही हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इस कानून से महिलाओं के खिलाफ हिंसा बेलगाम हो सकती है। काबुल की एक महिला कानूनी सलाहकार ने टाइला न्यूज को बताया कि महिलाओं के लिए न्याय पाना अब बेहद लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हो जाएगी। उन्होंने एक मामले का जिक्र किया, जिसमें एक महिला को जेल में बंद अपने पति से मिलने के दौरान बिना पुरुष संरक्षक के जाने पर पीटा गया। महिला ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस प्रक्रिया से गुजरने से बेहतर मौत को समझती है।

वेस्ट बैंक में जमीन पर कब्जे की तैयारी में इजरायल

येरूशलम, एजेंसी। इजरायल सरकार ने पश्चिमी तट में जमीन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के हालिया फैसले की आठ मुस्लिम देशों द्वारा निंदा करने वाले संयुक्त बयान को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया है। मंगलवार को तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने पश्चिमी तट में जमीन को सरकारी सम्पति घोषित करने और उनके पंजीकरण और मालिकाना हक के सेटलमेंट के लिए प्रक्रिया को मंजूरी देने के इजरायली सरकार के फैसले की निंदा की। मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा, 'यह बयान असल में बेबुनियाद और जानबूझकर गुमराह करने वाला है। फिलिस्तीनी अधिकारी ही क्षेत्र सी में गैर-कानूनी जमीन पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे है, जो कानून और मौजूदा समझौतों का उल्लंघन है।' मंत्रालय ने बताया कि इजरायली सरकार ने सिविल और सम्पति कानून के तहत प्रशासनिक कदम को मंजूरी दी है। सऊद अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह कदम कब्जे वाले इलाके में एक नई कानूनी और प्रशासनिक हकीकत को थोपता है, जिससे द्वि-राष्ट्र समाधान और फिलिस्तीनी अधिकार कमज़ोर होते हैं। मंत्रालय ने कहा कि फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायल का कोई हक नहीं है। मंत्रालय ने इन कदमों को फिलिस्तीनी लोगों के चार जून, 1967 की सीमाओं पर एक आजाद देश बनाने के कानूनी हक पर हमला बताया, जिसकी राजधानी पूर्वी येरुशलम हो। उल्लेखनीय है कि इजरायली सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बड़े इलाकों को अपनी भूमि के तौर पर वर्गीकृत करने की योजना को मंजूरी दी, अगर फिलिस्तीनी मालिकाना हक साबित नहीं कर पाते। यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी मंत्रियों बेज़ालेल स्मोट्रिच (वित्त), यारिव लेविन (न्याय), और इजरायल काट्ज (रक्षा) ने रखा था। स्मोट्रिच ने इस योजना को 'हमारी सभी जमीनों पर नियंत्रण करने के लिए समाधान क्रांति' का अगला कदम बताया, जबकि लेविन ने इसे इज़रायल के अपने सभी हिस्सों पर अपनी पकड़ मज़बूत करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन बताया। इस मंजूरी से ज़मीन के मालिकाना हक के समाधान की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई हैं, जो 1967 में वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे के बाद से रुके हुए थे।

चीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए तैयार

बीजिंग, एजेंसी। तारिक रहमान के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने पर चीन एक्टिव हो गया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने मंगलवार को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई दी और कहा कि बीजिंग ढाका के साथ मिलकर बीआरआई प्रोजेक्ट्स समेत सभी सेक्टर में आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए तैयार है, ताकि उनके रिश्ते एक नए लेवल पर पहुंच सकें। ली ने रहमान को अपने मैसेज में कहा कि चीनी सरकार नई बांग्लादेशी सरकार के सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करती है, जिन्होंने आज दिन में शपथ ली थी।

उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के साथ पारंपरिक दोस्ती को आगे बढ़ाने, हाई-क्वालिटी बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने और सभी सेक्टर में लेन-देन और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ली ने आगे कहा कि इससे चीन-बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंचेगी और दोनों देशों के लोगों को ज्यादा फायदे होंगे।

ली ने कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना लेन-देन, एक-दूसरे का सम्मान करने और विन-विन सहयोग का लंबा इतिहास रहा है। 12 फरवरी को हुए 13वें पार्लियामेंट्री चुनाव में अपनी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की जीत के बाद फॉरेन पॉलिसी पर अपनी पहली टिप्पणी में, रहमान ने कहा कि वह दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने में बांग्लादेश के हितों को प्राथमिकता देंगे। रहमान के हवाले से कहा गया, 'बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी फॉरेन पॉलिसी तय करेंगे।

चीनी सरकारी मीडिया ने रहमान की इस बात को हाईलाइट किया कि चीन को लंबे समय से बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर माना जाता है और उम्मीद जताई कि दोनों देश कॉमन डेवलपमेंट के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के अलावा, चीन के प्रति रहमान की सरकार की पॉलिसी इसलिए भी अहम हो गई क्योंकि अंतरिम सरकार के चीफ मुहम्मद यूनुस, जिन्होंने शेख हसीना को हटाने के बाद अगस्त 2024 में सत्ता संभाली, ने चीन और पाकिस्तान के पक्ष में पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, जिससे भारत के साथ ढाका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा।

ट्रम्प ने जापान के साथ ट्रेड डील के शुरूआत की घोषणा की

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को जापान के साथ एक निवेश समझौते के शुरूआत का एलान किया है। जापान ने अमेरिका में कुल 550 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, जो ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के अंत तक, यानी जनवरी 2029 तक पूरा होगा। यह समझौता पिछले साल जुलाई में हुआ था, जिसमें जापान ने अमेरिका में निवेश करने के बदले अपनी कारों और अन्य सामानों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ को कम करवाया था। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके बताया कि इस 550 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के तहत पहली परियोजनाओं की शुरुआत हो गई है। इनमें तीन बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 36 बिलियन डॉलर है। पहली परियोजना जॉर्जिया राज्य में क्रिटिकल मिनरल्स की है, जहां सिंथेटिक डायमंड या अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन होगा, जो अमेरिका की विदेशी निर्भरता कम करने में मदद करेगा। दूसरी परियोजना टेक्सास राज्य में तेल और गैस की सुविधाओं की है, जिसमें गल्फ कोस्ट पर एक डीपवॉटर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट सुविधा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (स्र्न्नत) प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो अमेरिकी ऊर्जा निर्यात को बढ़ावा देंगे। तीसरी परियोजना ओहियो राज्य में पावर जेनरेशन प्लांट की है, जो एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस पावर प्लांट होगा। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर के हैं और इन्हें लागू करने में टैरिफ की अहम भूमिका रही है। उन्होंने इसे अमेरिका और जापान के लिए ऐतिहासिक समय बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका फिर से निर्माण कर रहा है, उत्पादन कर रहा है और जीत रहा है। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में जापान के उद्योग मंत्री रयोसी अकाजावा और अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के बीच बैठक हुई थी, जहां पहले दौर के निवेश में तेजी लाने पर सहमति बनी। ये निवेश रणनीतिक क्षेत्रों जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा पर केंद्रित हैं, जो दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को मजबूत करेंगे।

न्यूयॉर्क में चर्च में धमाका, फायरफाइटर समेत पांच लोग घायल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क के एक चर्च में एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें एक फायरफाइटर समेत पांच लोग घायल हो गए। बिल्डिंग में गैस की गंध की रिपोर्ट मिली थी जिसके बाद अग्निशमन विभाग यहां आया था। न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस धमाके के कारण की जांच कर रही थी, जो सिरैक्यूज़ से लगभग 50 मील (80 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में एक ग्रामीण इलाके में एबंडेंट लाइफ फेलोशिप चर्च में सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। पांच लोगों को इलाज के लिए लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। दो की हालत गंभीर बताई गई, जिसमें एक फायरफाइटर भी शामिल है जो मौके पर पहुंचा था। पुलिस ने बताया कि बाकी तीन लोगों की चोटों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि धमाके से जुड़ी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का शुरुआती संकेत नहीं मिला, जिससे हवा में काले धुएं का घना गुबार फैल गया और चर्च को बहुत नुकसान हुआ। स्टेट ट्रूपर्स के अनुसार, चर्च को प्रोपेन सिलेंडर से गर्म किया जाता था।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत मामले में ठेकेदारों को नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 2 ठेकेदार और एक सहायक ठेकेदार को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। एडिशनल सेशन जज हरलीन कौर ठेकेदार हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थीं। इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी किए थे और कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी की देर रात कमल भयानी (25) की दिल्ली में जल बोर्ड की कंस्ट्रक्शन साइट पर खोदे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। 6 फरवरी की सुबह 8 बजे पीसीआर कॉल मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद हादसे का पता चला। जांच एजेंसी को उनसे कस्टडी में पूछताछ करनी है। जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, और जांच एजेंसी केस से जुड़ी जरूरी चीजें इकट्ठा करने में जुटी हैं। कहा जाता है कि एप्लीकेंट जांच एजेंसी की पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था और टालमटोल कर रहा था। अपराध की गंभीरता और उसके सामाजिक असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस एप्लीकेशन को मंजूरी देने का कोई आधार नहीं बनता। आवेदक की मौजूदा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज की जाती है।

पंजाब में सिविल और मिनी सचिवालय सहित पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब में सिविल सचिवालय और मिनी सचिवालय के साथ पुलिस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद गुरुवार को पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन मुख्य द्वारों को बंद कर लोगों के प्रवेश और निकास पर रोक लगा दी। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गईं। परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति की सख्ती से जांच की जा रही है। संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। सूत्रों के अनुसार धमकी किसी संदेश या ईमेल के माध्यम से मिली है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता।

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौत, इलाके में पसरा मातम

मथुरा (एजेंसी)। यूपी के मथुरा जिले के नगला दैवीया के पास एक तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार चार युवकों की मौके मौत हो गई। मृतकों में तीन युवक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा बुधवार शाम को हुआ। मारुति कार में सवार चार दोस्त किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महावन जा रहे थे। नगला दैवीया के पास कार की रफ्तार तेज होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही मगोर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से कार को नहर से बाहर निकाला। कार के अंदर फंसे युवकों को जब तक बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थीं। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए युवकों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि एक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मृतकों में राहुल वर्मा (23) निवासी महावन, पेशे से दर्जी। अमित (23) निवासी प्रेमनगर कलां, छात्र और मोहित (22) निवासी महावन, ला का छात्र था। बताया जा रहा है कि जिस कार से हादसा हुआ, वह राहुल वर्मा के भाई सज्जन सिंह की थी। एसपी देहात ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है। एक साथ चार युवकों की मौत से महावन और बलदेवगढ़ में सन्नाटा पसरा है।

10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां... दिल्ली सरकार करेगी जब्त

-दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी की सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी में तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अब 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जिन्हें 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' माना गया है, बिना किसी पूर्व नोटिस के जब्त हो सकती हैं। यह कार्रवाई केवल सड़कों पर चल रही गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पार्किंग, खुले मैदान या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खड़े वाहनों पर लागू होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को दिल्ली में रखने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी गाड़ियां राजधानी में दिखाई देती हैं, तब उन्हें कानून के तहत जब्त कर सीधे स्क्रैप (कबाड़) के लिए भेजा जा सकता है। यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण मानकों के सख्त पालन के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पुरानी गाड़ियों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर उन्हें दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करा लें। इससे वे जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीएस-3 और उससे नीचे के उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें हटाया जाएगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों की जानकारी समय रहते प्राप्त करें और आवश्यक कदम उठाएं, ताकि अचानक होने वाली कार्रवाई से किसी प्रकार की असुविधा न हो।

'वंदे मातरम' विवाद पर शशि थरूर... देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने 'वंदे मातरम' को लेकर चल रही बहस पर साफ कहा कि किसी भी नागरिक को गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस की आलोचना कर कहा कि देशभक्ति दिल से होती है, और कानून बनाकर इस गाने को जबरन किसी की जुबान पर नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा गाना अनिवार्य होगा।

कांग्रेस नेता थरूर ने इस दौरान 'वंदे मातरम' के इतिहास का उल्लेख किया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों को प्रेरित करता था। उन्होंने कहा कि आज एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में राज्य और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'वंदे मातरम' गाती थी, लेकिन देश की धार्मिक विविधता को देखकर 'जन गण मन' को राष्ट्रगान चुना गया। संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का समान दर्जा दिया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका सम्मानित हो और किसी समुदाय को अलग-थलग न किया जाए। यह एक सोच-समझकर किया गया समझौता था।

कांग्रेस नेता थरूर ने रवींद्रनाथ टैगोर की भूमिका का भी जिक्र किया। टैगोर ने 1896 में गीत को संगीतबद्ध किया और 1937 में सुझाव दिया कि सार्वजनिक मंचों पर केवल पहले दो अंतरे गाए जाएं। शुरुआती पंक्तियां मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीकात्मक वर्णन करती हैं, जिसे सभी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन बाद के अंतरों में दुर्गा और लक्ष्मी जैसी देवी-देवताओं का उल्लेख है, इससे कुछ धर्मों के लोग धार्मिक कारणों से नहीं गा सकते। कांग्रेस नेता थरूर ने कहा कि कई मुस्लिम नागरिकों की आपत्ति इसी कारण है, क्योंकि इस्लाम में तौहीद के सिद्धांत के अनुसार किसी अन्य ईश्वर या देवी-देवता को मानना या उसकी स्तुति करना स्वीकार्य नहीं है।

कांग्रेस सांसद थरूर ने मोदी सरकार के हालिया आदेश पर भी सवाल उठाकर कहा कि किसी प्रतीक की ताकत उसकी स्वैच्छिक श्रद्धा में है, जबरदस्ती पालन में नहीं। उन्होंने 1986 के सुप्रीम कोर्ट के 'जेहोवाज विटनेस केस' का उदाहरण दिया, जिसमें धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान न गाने वाले छात्रों को बहाल किया गया था। थरूर ने सुझाव दिया कि 'वंदे मातरम' विवाद में यही मॉडल अपनाया जाए—जो लोग पूरी श्रद्धा से गाना चाहते हैं, वे गाएं, और जिन्हें धार्मिक या अंतरात्मा की आपत्ति है, उन्हें चुपचाप सम्मान करने का अधिकार मिले, बिना दंड या सामाजिक बहिष्कार के। यह दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सोच-समझकर किया गया प्रयास है।

नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी... यात्रियों को लंबी लाइनों और देरी का सामना करना पड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह तकनीकी खराबी के चलते हड़कंप मच गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयरलाइंस द्वारा बुकिंग और चेक-इन के लिए इस्तेमाल होने वाले नेविटेयर सिस्टम के सर्वर में समस्या आ गई। इस वजह से यात्रियों को लंबी लाइनों और देरी का सामना करना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह खराबी सुबह करीब 6:45 बजे सामने आई और तकनीकी टीम ने करीब 7:30 बजे तक ठीक किया। इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी मैनुअल रूप से अपडेट करनी पड़ी, जिससे सुबह की भीड़ में असुविधा बढ़ गई और कुछ उड़ानें प्रभावित हुईं। इसतरह मुंबई एयरपोर्ट पर भी ऐसी स्थिति देखी गई। नेविटेयर सिस्टम की खराबी के कारण यात्रियों को चेक-इन काउंटर पर लंबा इंतजार करना पड़ा और भीड़भाड़ की शिकायतें सामने आईं। नेविटेयर सिस्टम एयरलाइन टिकट बुकिंग, चेक-इन और बोर्डिंग जैसी सुविधाओं के लिए अत्यंत जरुरी है। इसके ठप होने पर एयरलाइंस यात्रियों को समय पर सेवा देने में असमर्थ होती हैं, इससे देरी और अव्यवस्था होती है। बीते साल नवंबर में भी कई एयरपोर्ट पर तकनीकी गड़बड़ी के मामले सामने आए थे। दिल्ली के आईजीआईए पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली में खराबी के कारण उड़ान संचालन बाधित हुआ था। इसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया था। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए तकनीकी सिस्टम की स्थिरता बेहद जरूरी है, और ऐसी खामियों से यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ती है। कुल मिलाकर, गुरुवार की यह तकनीकी दिक्कत यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बनी, लेकिन तकनीकी टीम की त्वरित कार्रवाई से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ गई।

संजय राउत के बयान पर पवन खेड़ा कि प्रतिक्रिया... उनके बयान पर इंडिया ब्लॉक में विचार होगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी संजय राउत के हालिया बयान पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा, वह एक वरिष्ठ नेता हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है, तब निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी इस बयान के बारे में विचार कर तय करने वाले हैं कि क्या किया जाए है। इसके पहले शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इंडिया ब्लॉक के कामकाज की आलोचना कर आरोप लगाया कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर ही सक्रिय होता है और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार समन्वय का अभाव है।

मुंबई में राउत ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का काम लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर शुरू होता है। तब तक किसी के बीच कोई संवाद नहीं होता। तब तक इंडिया ब्लॉक में जनता क्या कर रही है, यह किसी को नहीं पता होता। उन्होंने इस जोर दिया कि संसद के अंदर मुद्दों को उठाना ही काफी नहीं है, खासकर तब जब विपक्षी नेताओं को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र कर राउत ने कहा, वे राहुल गांधी को संसद में बोलने तक नहीं देते। क्या हम बाहर कुछ कर सकते हैं?

राउत ने तर्क दिया कि गठबंधन को पूरे राजनीतिक चक्र में सक्रिय रहना चाहिए, न कि केवल आम चुनाव से पहले। उन्होंने किसानों की परेशानी, कानून व्यवस्था और मणिपुर की स्थिति सहित कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया, जिन पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं।

पीएम मोदी ने रामकृष्ण को स्वामी कह संबोधित किया, ममता का आरोप... बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। सीएम ममता ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहकर संबोधित किया, जो बंगाल की सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ है और महान संत के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता को दिखाता है। ममता बनर्जी ने पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताकर कहा कि यह अभूतपूर्व और अनुचित संबोधन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में रामकृष्ण परमहंस को व्यापक रूप से ठाकुर या श्री रामकृष्ण के रूप में पूजा जाता है। ममता ने कहा कि परमहंस के देहांत के बाद उनके तपस्वी शिष्यों ने रामकृष्ण मठ और मिशन का गठन किया था, जिन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार स्वामी कहा गया। लेकिन स्वयं आचार्य या गुरु

को हमेशा ठाकुर कहा जाता रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान को बंगाल की संस्कृति और परंपराओं की समझ की कमी बताकर अनुचित बताया।

दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार को रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने लिखा कि उनके आध्यात्मिक विचार और संदेश हमेशा मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहने वाले है।

रामकृष्ण परमहंस (1836-1886) दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे और विभिन्न धर्मों की एकता तथा आध्यात्मिक सद्भाव का संदेश देने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद प्रमुख थे, जिन्हें स्वामी उपाधि से संबोधित किया गया। वर्तमान में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ उनकी शिक्षाओं पर आधारित सक्रिय संस्थाएँ हैं। बंगाल में वे ठाकुर के रूप में सम्मानित हैं, इसलिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के संबोधन को सांस्कृतिक दृष्टि से असंवेदनशील करार दिया। इस विवाद ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के सही प्रयोग पर बहस को फिर से उभारा है, खासकर उन संदर्भों में जहाँ सार्वजनिक नेताओं द्वारा संतों और आचार्यों को संबोधित किया जाता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में टेका माथा, वीडियो वायरल

नई दिल्ली (एजेंसी)। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में भाग लेने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब में माथा टेका और श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया जो भारत-फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों की इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां वे एक वैश्विक नेता के साथ-साथ एक श्रद्धालु के रूप में नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब के प्रबंधन ने भी उनके आगमन पर विशेष ध्यान दिया और इस यात्रा को यादगार बना दिया। उन्होंने वहां सिख समुदाय की परंपराओं को देखा और श्रद्धा भाव के साथ अपनी प्रार्थना की। इससे पहले दौरे के दौरान उन्होंने दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह का भी दौरा किया था।

मुस्लिम आरक्षण रद्द करने पर भड़की कांग्रेस ने कहा- बदले की राजनीति के सिवाए कुछ नहीं

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के 2014 के पुराने आदेश को औपचारिक रूप से रद्द करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। जहाँ सत्ता पक्ष इसे केवल एक कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकता बता रहा है, वहीं विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है।

यह विवाद 2014 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत और मुस्लिम समुदाय को विशेष पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस नीति को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसने मराठा आरक्षण को तो खारिज कर दिया था, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम आरक्षण को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में आई भाजपा-शिवसेना सरकार ने इस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं दिया, जिससे यह समय सीमा समाप्त होने के बाद निष्प्रभावी हो गया था। अब वर्तमान सरकार ने उसी पुराने आदेश (जीआर) को आधिकारिक रूप से रद्द करने का प्रस्ताव जारी किया है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से शपथ के समय सभी के प्रति निष्पक्ष रहने और संविधान का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उच्च न्यायालय ने कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया था, तब भी इसे रद्द करना सरकार की भेदभावपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का तर्क है कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता और 2014 का वह आदेश तकनीकी रूप से पहले ही खत्म हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम में उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) शिवसेना का रुख चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के महीनों में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नरम रुख दिखाने वाली पार्टी ने इस मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पार्टी सांसद संजय राउत ने केवल इतना कहा कि इस विषय पर बाहर चर्चा करने के बजाय आगामी विधानसभा सत्र में अपनी बात रखी जाएगी। वहीं, शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरक्षण का यह मुद्दा राज्य में ध्रुवीकरण और तीखी राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है।

असम में तीसरी बार सत्ता में वापसी को जुटा भगवा दल... कांग्रेस की राह नहीं दिख रही आसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। असम में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के लिए यहां सत्ता बचाने की चुनौती है। भगवा गुट यदि असम में सरकार बनाने में सफल होता है, तब असम में यह भगवा गुट की हैट्रिक होगी। भाजपा ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को असम विधानसभा में 50 प्रतिशत वोट लाने का लक्ष्य दे दिया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में में बीजेपी का वोट शेयर 33.2 प्रतिशत था। वहीं, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को तब जबरदस्त झटका लगा जब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी।

भाजपा अध्यक्ष नवीन के द्वारा दिए गए टारगेट को अगर बीजेपी हासिल कर लेती है, तब असम में सभी दलों का सूपड़ा साफ कर देगी। विपक्ष सिर्फ 20-28 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की लोकप्रियता अभी भी कायम है। वहीं सत्ता में वापस आने के लिए व्याकुल दिख रही कांग्रेस की असम विधानसभा की राह आसान नहीं है। वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा के इस्तीफे से जहां पार्टी आंतरिक चुनौती से जूझ रही है, वहीं महाजोत में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने को लेकर महाजोत के कई घटकदल दबाव बनाए हुए हैं। असम में अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं।

तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस असम में पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही। तमाम कोशिशों के बाद भी बोरा ने आखिरकार पार्टी छोड़ दी। पार्टी को डर है कि भूपेन बोरा के साथ उनके भरोसेमंद कई विधायक और नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे मतदाताओं में पार्टी की छवि कमजोर होगी। इसके साथ महाजोत में सीट बंटवारा भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि, 2021 के महाजोत में कई बदलाव हुए हैं। एआईयूडीएफ और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) दोनों महाजोत से अलग हो चुके हैं। बीपीएफ अब एनडीए का हिस्सा है, वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल की अगुआई में एआईयूडीएफ अपने दम पर चुनाव लड़ेगा।

वहीं, असम जातीय परिषद और अखिल गोगोई का रायजोर दल अब महाजोत में शामिल हैं। कांग्रेस ने एजेपी और रायजोर दल दोनों को महाजोत में 11-11 सीट देने की पेशकश की है, पर दोनों दल इससे ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस इन्हें अधिक सीट देती है, तब चुनाव में कांग्रेस को कम सीट पर लड़ना होगा। असम में दूसरे दलों के साथ गठबंधन किए बगैर भाजपा की अगुआई वाले एनडीए को शिकस्त देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।

अरुणाचल के करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा चीन, भारत के लिए खतरे की घंटी

-चीन का यह परमाणु विस्तार दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की सेना न्यूक्लियर हथियारों के दम पर डराने के पैंतरे आजमा रही है। दुनिया की नजरों से छुपकर चीन के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसका कच्चा चिट्ठा अब सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दिया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा है। चीन की यह गुस्ताखी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 800 किलोमीटर दूर चीन के सिचुआन प्रांत में परमाणु ताकत का विस्तार चल रहा है, जिसका पर्दाफाश सैटेलाइट तस्वीरों ने किया है। इन फोटोज में चीन का वह गुप्त साम्राज्य दिख रहा है जहां न केवल नए परमाणु हथियार बन रहे हैं बल्कि उन्हें और भी घातक बनाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है, जहां रूस और अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म हो चुकी है, दूसरी तरफ चीन का यह बेलगाम परमाणु विस्तार दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सिचुआन की पहाड़ियों में छिपे ये ठिकाने सीधे तौर पर भारत के पूर्वी इलाकों के लिए रेड अलर्ट हैं।

सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सिचुआन की घाटियों में दो प्रमुख जगहों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जितोंग घाटी में नए बंकर और मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क देखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जगह का उपयोग हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है, जो परमाणु वारहेड को ट्रिगर करने के लिए जरूरी है। पिंगटोंग घाटी में प्लूटोनियम पिट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो परमाणु बम का कोर होते हैं, यहां की सुरक्षा इतनी सख्त है कि यह किसी किले जैसी दिखती है।

बता दें सिचुआन, अरुणाचल प्रदेश से भौगोलिक रूप से सिर्फ 800 किमी दूर है। चीन ने पहले ही अरुणाचल को अपना 'कोर इंटरेस्ट' घोषित कर दिया है। परमाणु शक्ति का विस्तार चीन को सीमा पर एडवांटेज देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपने परमाणु जखीरे को इसलिए बढ़ा रहा है ताकि वह अमेरिका और भारत जैसे देशों को अपने परमाणु हथियारों की पोजीशन दिखाकर डराने की स्थिति में ला सके। 2026 की शुरुआत तक चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु वारहेड हो चुके हैं और 2030 तक यह संख्या 1,000 के पार जाने का अनुमान है। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है।